

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256

DAVP Code : 128101

Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05

Posting Date : Every Month Dt. 15

Rs. 10/-

जगत विजय

वर्ष : 25 अंक : 2

5 अक्टूबर 2024



कैलाश विजयवर्गीय बने भारत के पहले ग्रीन पॉलिटिशियन

पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए विजयवर्गीय को
मिलना चाहिए गोल्डमैन पर्यावरण और पद्मश्री पुरस्कार



प्रेरणा स्रोत : स्व. श्री जगत पाठक



निर्भीक पत्रकारिता

संपादक विजया पाठक
कार्यकारी संपादक समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज
एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लॉट नं. 28 सुरभि विहार
बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17,
शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया
पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय
रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख
एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in



कैलाश विजयवर्गीय बने भारत
के पहले ग्रीन पॉलिटिशियन

पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए विजयवर्गीय को
मिलना चाहिए गोल्डमैन पर्यावरण और पद्मश्री पुरस्कार

(पृष्ठ क्र.-6)

- वन नेशन-वन इलेक्शन, मोदी की राह मुश्किल !27
- 2029 में एक-देश, एक-चुनाव, संयुक्त चुनाव कराने की तैयारी37
- छत्तीसगढ़वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए
अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत40
- राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा और उससे उपजे सवाल44
- क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका डेलावेयर में भारत का आगाज़48
- तिरुपति के प्रसाद में पशु चर्बी: गरमाई सियासत51
- साई बाबा किसी एक के नहीं सबके हैं55
- क्या मणिपुर और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति
कायम करना चाहती है भाजपा59
- Does today's Indian democracy pass the Ambedkar test?.....62





तिरुपति मंदिर का प्रसाद अपवित्र : आहत हुई भावनाएं

तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने वाले घी में मछली का तेल, सुअर और गाय की चर्बी मिलाए जाने की बात सामने आने के बाद लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुपति मंदिर के लड्डू पर किए गए खुलासे ने नई बहस छेड़ दी है। लड्डू बनाने के लिए अशुद्ध घी के इस्तेमाल के लिए जगनमोहन रेड्डी की तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह मुद्दा इसलिए भी गरमाया है क्योंकि तिरुपति मंदिर का प्रसादम पूरे देश में अपने अलग स्वाद के लिए जाना जाता है। यह पूरा मामला तब चर्चा में आया जब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि, प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने में पशु मांस का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, राज्य में पिछली वार्डएसआरसीपी सरकार के दौरान प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू, बनाने में घटिया सामग्री और पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था। सीएम ने एक लैब टेस्ट रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि, टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि, तिरुपति के प्रसिद्ध वेकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू को बनाने के लिए गोमांस की चर्बी, मछली के तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आश्वासन दिया कि, तिरुमाला लड्डू में पशु वसा की मिलावट के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि, पिछली सरकार ने तिरुमाला में प्रसाद को नष्ट कर दिया था और टीडीपी सरकार ने पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए सुधार कार्य शुरू किए हैं। दरअसल, टीटीडी बोर्ड हर साल लगभग पांच लाख किलो घी खरीदता है। इस हिसाब से हर महीने लगभग 42,000 किलोग्राम घी खरीदा जाता है। घी की खरीद के लिए हर 6 महीने में टेंडर जारी किया जाता है। घी के अलावा टीटीडी को लगभग 22,500 किलोग्राम काजू, 15,000 किलोग्राम किशमिश और 6,000 किलोग्राम इलायची की भी ज़रूरत होती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि, पहले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन द्वारा घी की आपूर्ति की जाती थी। चार साल पहले आपूर्ति बंद कर दी गई थी। इसका कारण था घी की कीमत। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के अनुसार घी की कीमत को लेकर विवाद हुआ था, इसके बाद सप्लाई बंद कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की कंपनी नंदिनी, टीटीडी को कम कीमत पर घी देने में असमर्थ था। इसका कारण थी कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार। कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का आदेश दिया था। इस बीच, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तिरुपति मंदिर बोर्ड ने तमिलनाडु के डिंडीगुल के एक आपूर्तिकर्ता की ओर रुख किया, जिसके घी में कथित तौर पर पशु वसा के अंश पाए गए।

विजया पाठक



कैलाश विजयवर्गीय बने भारत के पहले ग्रीन पॉलिटिशियन

पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए विजयवर्गीय को
मिलना चाहिए गोल्डमैन पर्यावरण और पद्मश्री पुरस्कार

विज्ञान, धर्म, आस्था एवं आध्यात्म जब भी का मिलन होता है तो एक चमत्कार होता है। ऐसा ही एक चमत्कार इंदौर स्थित पितृ पर्वत नाम से हुआ है। कोई 22 वर्ष पहले इंदौर शहर के राजनीतिज्ञ कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा संकल्प लिया जिससे इंदौर शहर के इस स्थान से पूरे वर्ष में 2500 करोड़ लीटर आक्सीजन प्रतिवर्ष मिलती है। आध्यात्मिक तौर पर एक विचार शून्य जगह, आस्था से चमत्कारिक पितृश्वर हनुमान जी मंदिर, गौ सेवा के साथ आध्यात्मिक पर्यटन का स्थान पितृ पर्वत के तौर पर दिव्य स्थान की संरचना की गई है। बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने वर्ष 2002 में गोमटगिरी पहाड़ी के सामने देवधरम टेकरी पर बैठे हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाने का संकल्प लिया था। इसके साथ ही धर्म और विज्ञान को साथ लेते हुए पितृ पर्वत पर इंदौर के नागरिकों को प्रोत्साहित करके अपने पितरों की याद में 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं ताकि पर्यावरण की रक्षा के साथ लोगों की भावनाएं भी पितृ पर्वत से जुड़ी रहे। आस्था एवं धर्म के मुताबिक पितृदोष के चलते इंदौर शहर का समुचित विकास नहीं हो पा रहा था, पितृ पर्वत बनने के बाद यह दोष दूर हो गया है। आज विश्व में इंदौर की छवि स्वच्छतम शहर की है। साथ ही आज केवल पितृ पर्वत धाम से शहर को 2500 करोड़ लीटर ऑक्सीजन साल भर में मिलती है। साथ ही रेवती रेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर शहर में कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में 51 लाख पौधों का पौधारोपण किया जाना संकल्पित है। भविष्य में करीब-करीब 53.50 हजार करोड़ लीटर ऑक्सीजन प्रतिवर्ष इस पावन क्षेत्र से शहर को मिलेगी। अगर वैज्ञानिक तौर पर नापा जाए तो पौधारोपण के माध्यम से कार्बन सिक्वैस्ट्रेशन करके 12.75 लाख कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है। कार्बन क्रेडिट का मकसद ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है एवं इससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलती है। एक कार्बन क्रेडिट 1,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर माना जाता है एवं कार्बन क्रेडिट, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किए गए प्रयासों का प्रमाण पत्र है। कैलाश विजयवर्गीय का पर्यावरण प्रेम जनमानस की भावनाओं के अनुरूपता को ही प्रमाणित करता है। लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना और उनके ही सहयोग से इस पुनीत कार्य को संपूर्णता प्रदान करना कैलाश जी का ध्येय रहा है। यही कारण है कि आज देश के अंदर उनके जैसा काम कम ही लोग कर रहे हैं। वह जिस संकल्प और साधना को लेकर पर्यावरण को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं वह अनेकों लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। आज इंदौर शहर को अपने पर्यावरण के प्रति इतने वर्षों के तप के कारण कैलाश विजयवर्गीय को अंतराष्ट्रीय गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार मिलना चाहिए।

विजया पाठक

कैलाश विजयवर्गीय एक राजनीतिज्ञ, कर्मयोगी के साथ अध्यात्म की राह पर चलते-चलते पर्यावरणविद भी बन गए हैं।

इंदौर शहर के इस पावन क्षेत्र आज धार्मिक, अध्यात्म, सेवा एवं पर्यावरण संयोजन का प्रमुख केंद्र बन गया है। हनुमानजी की मूर्ति स्थापित होने के बाद इस स्थान का नया

नामकरण पितरेश्वर हनुमान धाम हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस मूर्ति की स्थापना नहीं होने तक 18 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया था। 18 साल बाद जब



उनका संकल्प पूरा हुआ तो उन्होंने अन्न ग्रहण किया था। अपने संकल्प के कारण देखते ही देखते एक राजनीतिज्ञ कैसे

पर्यावरणविद बन गए। ऐसे कर्मयोगी को पर्यावरण क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के साथ पद्मश्री से

अलंकृत करना चाहिए ताकि ऐसे अनूठे प्रयास एवं वर्षों की तपस्या का पुरस्कार मिल सके। मान्यता है कि पितरेश्वर हनुमान



राजनीतिज्ञ कर्मयोगी से पर्यावरणविद तक का सफर

कभी-कभी व्यक्ति की नियति उससे कुछ अलग ही कार्य करवा देती है, इसका एक उदाहरण भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। 2002 में इंदौर शहर के महापौर के तौर पर उन्होंने पितृ पर्वत पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने का प्रण लिया था और संकल्प लिया था कि तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। हालांकि उस समय उनका यह संकल्प धार्मिक था पर समय के साथ-साथ धीरे-धीरे इस संकल्प में पर्यावरण संरक्षण का भाग जुड़ता चला गया। शायद इसे ही नियति ही कहेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने प्रयासों के माध्यम से इंदौर शहर को पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मशहूर करके अब पर्यावरणविद भी बन गए हैं। इंदौर पिछले 10 वर्षों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है जिसका सबसे बड़ा श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को जाता है। पितृ पर्वत पर उनके अनूठी मुहिम जिसमें शहरवासी अपने पित्रों के नाम पर वृक्षारोपण करके कोई 22 वर्षों में 2,50,000 वृक्षों की एक बड़ी वानिकी पितृ पर्वत पर बन चुकी है। आज इंदौर शहर में कोई 2500 करोड़ लीटर ऑक्सीजन प्रतिवर्ष पितृ पर्वत देता है। इसके साथ ही रेवती रेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान 'एक पेड़ मां के नाम' के अंतर्गत 51 लाख पौधारोपण कर विश्व कीर्तिमान बनाया गया है। यानी भविष्य में इस क्षेत्र से ही 53.50 हजार करोड़ लीटर प्राणवायु ऑक्सीजन प्रतिवर्ष इंदौर के लिए जीवन वाहिनी बनेगी। इस मुहिम को अपनी तन्मयता से पूरा करके आज कैलाश विजयवर्गीय एक राजनेता की छवि से उपर एक पर्यावरणविद बन गए हैं, जिनके कारण इंदौर की आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा मिलती रहेगी।

के पूजा से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यहां जलने वाली जोत को राम नगरी अयोध्या से

लाया गया था। हनुमान जी पितृ पर्वत पर ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं और प्रभु राम की

भक्तिकर रहे हैं। ग्वालियर के 125 कारीगरों ने सात साल की कड़ी मेहनत कर हनुमान

कैलाश विजयवर्गीय संभवतः है देश के पहले ग्रीन पॉलिटिशियन

ग्रीन पॉलिटिक्स, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जिसका उद्देश्य ऐसे समाज को बढ़ावा देना है, जो पर्यावरण, अहिंसा, सामाजिक न्याय और जमीनी स्तर के लोकतंत्र में निहित हो। यकीनन कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों में अपना अदभुत योगदान देकर ग्रीन पॉलिटिशियन बन गये हैं। दुनिया के अन्य कई देशों में ग्रीन पॉलिटिशियन पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर चुके हैं जिनमें प्रमुखतः अर्नोल्ड



श्वार्ज़नेगर कैलिफोर्निया में, केन लिविंगस्टोन लंदन में, हेलेन क्लार्क न्यूजीलैंड में और मरीना सिल्वा ब्राज़ील में पर्यावरण के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। यह सूची काफी लंबी है जिनमें अलग-अलग देशों के राजनेताओं ने अपनी राजनीति के साथ पर्यावरण को सहेजने और हरित क्रांति को बढ़ावा देने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय के हरित संकल्प और प्रयासों ने इंदौर शहर की आबोहवा को एक नया जीवन प्रदान किया है। देश को इंताज़ार कर रहा है कैलाश विजयवर्गीय ग्रीन पॉलिटिशियंस अपनी ग्रीन पॉलिटिक्स से देश में हरियाली और स्वस्थ जलवायु की बहार ले आए।

अगर कोई राजनेता या राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ एक मुहिम चल जाती है। अखबार से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में चर्चा होती है और सब जुट जाते हैं, उसको रावण का दर्जा देने में। जब किसी बुरे को गलत साबित करने में इतनी फूर्ती दिखायी जाती है तो जब कोई नेता या राजनीतिज्ञ समाज के लिए कोई अनूठा काम करता है तो उस काम को उसकी जिम्मेदारी कह कर क्यो इतिश्री हो जाती है। क्यो उस राजनेता के कार्यों को अखबार से लेकर सोशल मीडिया में जगह नहीं दी जाती है।

जी की इस विशालकाय प्रतिमा का निर्माण किया था। यहां पर हनुमानजी की मूर्ति स्थापित होने के बाद इस स्थान का नया नामकरण पितरेश्वर हनुमान धाम हो गया है। यानी पितृ पर्वत अब पितरेश्वर हनुमान धाम

से जाना जाता है। यहां अब खूबसूरत हरियाली देखते ही बनती है।

72 फीट उंची है प्रतिमा- हनुमान जी की यह प्रतिमा अष्टधातु की बनी है और 72 फुट उंची है। बताया जाता है कि इस मूर्ति

का वजन करीब 108 टन है। इस मूर्ति के निर्माण में करीब 07 साल का समय लगा था। इस मूर्ति का निर्माण ग्वालियर के मूर्तिकारों ने करीब 7 साल में तैयार किया था। मूर्ति के पास 5 हाइमास्ट लगे हुए हैं।

यहाँ इस बात का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक कुशल राजनेता और लोकप्रिय जननेता पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए पिछले 22 वर्षों से सतत अग्रसर है लेकिन अभी भी उनके द्वारा किए गए ऐसे पवित्र कार्य को यथोचित स्थान नहीं मिल पाया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी की। वर्षों से राजनीति में रहते हुए, प्रमुख पदों पर आसीन रहने के बावजूद कैलाश जी के लिए पर्यावरण संरक्षण का यह सफर आसान नहीं रहा है। कभी विपक्ष ने उनके कार्यों को पब्लिसिटी स्टंट कहा तो कभी लोगों ने इसे सत्ता का उपयोग कर अपना वर्चस्व बढ़ाना कहा। लेकिन कैलाश जी ने कभी व्रत से तो कभी संकल्प से, कभी आग्रह से तो कभी आदेश से, सारे जतन और यतन के बाद इंदौर शहर को स्वच्छ और हरित वातावरण की गोद नसीब करवायी है। राजनेता होना और राजनीति में बड़ा पद

पाना शायद हर उस व्यक्ति का सपना होता है जो राजनीति में हाथ आजमाना चाहता है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के लिए लगता है कि जननेता होना एक परीक्षा जैसा हो गया अन्यथा अगर वो कोई साधारण मानस होते तो उनके द्वारा पर्यावरण के लिए किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए उनको एक अलग पहचान भी मिली होती और अनगिनत सम्मान भी दिए जाते। यहाँ अनेक उदाहरण उपस्थित हैं जिनके पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए छोटे से छोटे



कार्य भी सराहे गए हैं और उनकी मिसालें भी बनी हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर शहर में हरियाली के विस्तार और बचाव कार्य किए जिसकी वो मिसाल भी हैं और अनुकरणीय भी हैं। यहाँ यह कहना कि अगर कैलाश विजयवर्गीय के पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे योगदान को पहचान ना मिली तो क्या उनके कार्यों में ठहराव आ जाएगा नहीं कतई नहीं। वो अपने संकल्प के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। लेकिन सम्मान, स्वीकार्यता और पहचान ना सिर्फ संकल्पित व्यक्ति का मनोबल बढ़ाती है बल्कि अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बनती है। आज एक कैलाश विजयवर्गीय ने अपने शहर की तस्वीर बदलने की ठानी है, अगर उनके कार्यों को सराहा जाए, उन्हें सम्मानों से नवाजा जाए तो ऐसे अन्य कई कैलाश विजयवर्गीय खड़े हो जाएंगे, अपने समाज और शहर की तस्वीर बदलने के लिए। सम्मान और सराहना बड़ी संक्रामक होती है अगर फैलती है तो कई लोगों की सोच और समझ में बदलाव लाती है। आज वह समय आ गया है कैलाश विजयवर्गीय के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को देश सम्मान और पहचान दोनों प्रदान करना चाहिए और उनके विश्व पटल पर गौरवान्वित होने के अवसरों को सुदृढ़ बनाये।

जिस कारण से मूर्ति के आसपास दिन-रात एक जैसा माहौल रहता है।

पौधा लगाते हैं लोग- पितरों की स्मृति में यहाँ एक लाख पौधारोपण किया गया है। श्री पितरेश्वर हनुमान जी की प्राण-प्रतिष्ठा

कर उन्हें जागृत किया गया है। यहां प्राचीन शिव मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार होने के बाद ही धाम का निर्माण पूर्ण हो पाया। यहां प्राचीन सिद्ध भैरव मंदिर है। मान्यता है कि भैरव की उत्पत्ति शिव के रुधिर से हुई थी।

यहां हनुमान जी की दो प्रतिमाएं विराजित हैं। एक मूर्ति की पूजा होती है जबकि एक के दर्शन किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देश सहित मध्यप्रदेश में भी एक पेड़ माँ के नाम

कार्बन पृथक्करण/कार्बन सीक्वेट्रेशन करके इंदौर पितृ पर्वत पर हुए वृक्षारोपण से हासिल करेगा 12.75 लाख कार्बन क्रेडिट

पितृ पर्वत पर पिछले 22 सालों में करीब 2.5 लाख घने वृक्षों की वानिकी बन गई है। इस व्यापक वृक्षारोपण के बाद कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में 51 लाख वृक्षों का संकल्प निश्चय किया है। इस व्यापक स्तर पर हुए वृक्षारोपण से कार्बन क्रेडिट हासिल कर आर्थिक लाभ भी उठाया जा सकता है, जिसके लिए कार्बन पृथक्करण/कार्बन सीक्वेट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को हटाने और उसे संग्रहित करने की प्रक्रिया है। जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनाए जा रहे कई तरीकों में से एक है। पृथ्वी के वायुमंडल को और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए कार्बन-उत्सर्जक ईंधन एवं कार्बन डाइऑक्साइड पर हमारी निर्भरता एवं कम करने की दिशा में बाध्यकारी शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य स्थापित करने तक करने के लिए वृक्षारोपण एक तरीका है। अगर हम अभूतपूर्व जलवायु परिवर्तन को रोकना चाहते हैं तो हर संभावित समाधान की तरफ सोचना होगा। स्वच्छ उर्जा प्रणालियों में बदलाव और उच्च-उत्सर्जन प्रथाओं-जैसे निर्माण या परिवहन- को डीकार्बोनाइज़ करने के साथ-साथ, मानव जाति अपने वायुमंडल से CO₂ को हटाने के लिए एक ठोस प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए हमें निर्माण, उपभोग, यात्रा और बिजली उत्पादन के तरीकों में बदलाव करना होगा। कार्बन पृथक्करण जैसे तरीके बताते हैं कि हम जलवायु संकट से निपटने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के साथ कैसे काम कर सकते हैं। कार्बन पृथक्करण पृथ्वी के वायुमंडल से CO₂ को पकड़ना, हटाना और स्थायी रूप से संग्रहित करना है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन हटाने की एक प्रमुख विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित CO₂ का लगभग 45 प्रतिशत वायुमंडल में रहता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक है। कार्बन पृथक्करण ग्रह के तापन में योगदान देने वाले आगे के उत्सर्जन को रोक सकता है।

जैविक कार्बन पृथक्करण तब होता है जब CO₂ प्राकृतिक वातावरण में संग्रहित होता है। इसमें 'कार्बन सिंक' के रूप में जाने वाले क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि जंगल, घास के मैदान, मिट्टी, महासागर और पानी के अन्य निकाय। इसे पृथक्करण का 'अप्रत्यक्ष' या निष्क्रिय रूप भी कहा जाता है। जंगलों वन और वानिकी को प्राकृतिक कार्बन पृथक्करण के सर्वोत्तम रूपों में से एक माना जाता है। जैसा कि इंदौर शहर में कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में पितृ पर्वत एवं आसपास के क्षेत्र में 53.50 लाख वृक्ष संकल्पित है। औसतन, वन जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं, उससे दुगुना कार्बन संग्रहित करते हैं, जबकि वैश्विक CO₂ उत्सर्जन का अनुमानतः 25 प्रतिशत भाग वनों के साथ-साथ अन्य वनस्पति रूपों, जैसे घास के मैदानों या चारागाहों (खेत, मैदान, झाड़ियाँ आदि) में संग्रहित हो जाता है। इसलिए ऐसे प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना कार्बन सिंक को प्रभावी ढंग से CO₂ को पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।

का अभियान चलाकर लाखों की संख्या में पौधारोपण किया गया। यह पहल पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को लेकर थी। और इस अभियान का उद्देश्य अधिक से

अधिक संख्या में पौधारोपण करना था। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि जिस संकल्पना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुहिम छोड़ी और पर्यावरण संरक्षण की चिंता

जाहिर की उस चिंता को मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय वर्षों पहले समझ चुके थे। विजयवर्गीय इंदौर के

रेवती रेंज में 51 लाख वृक्षारोपण के बाद बड़ा सकारात्मक पर्यावरण इंपैक्ट आयेगा इंदौर शहर पर

रेवती रेंज में 11 लाख वृक्षारोपण के विश्व कीर्तिमान के बाद कुल मिलाकर 51 लाख वृक्षारोपण संकल्पित है। इस बड़े पर्यावरण संरक्षण महायज्ञ के प्रणेता कैलाश विजयवर्गीय रहे हैं। आने वाले दिनों में रेवती रेंज वृक्षारोपण के कारण इंदौर शहर में बड़ा सकारात्मक इंपैक्ट चेंज आने वाला है। प्रदूषण के कारण आज मौजूदा समय में हम इंसानों में विभिन्न गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हुई है। पर्यावरण संबंधी इस बड़े महायज्ञ के कारण इंदौर और उसके आस पास के क्षेत्र के रहवासी आने वाले वर्षों में अच्छी पर्यावरण कवर के कारण स्वस्थ जीवन हासिल करेंगे। पितृ पर्वत एवं रेवती रेंज में कुल 54 लाख वृक्षारोपण के कारण इंदौर और उसके आस पास के क्षेत्र में में कुल 5-7 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। इसके अलावा वायु प्रदूषण में भी जबरदस्त कमी आएगी। एम्बिएंट एयर क्वालिटी में इजाफा होगा। कुल मिलकर इंदौर की हवा साफ, निर्मल और स्वच्छ हो जाएगी। रेवती रेंज जहां अभी तक 11 लाख वृक्षारोपण हुआ है वहां पर 40 लाख वृक्षारोपण संकल्पित है। आज के दिन बंजर समान इस क्षेत्र की मिट्टी/मृदा को पोषण तत्व मिल जाएंगे एवं इनकी स्वाइल ऑर्गेनिक कार्बन 805 किलो/वर्ग मी/साल बढ़ जाएगा।

SN	Species	Number of plants planted	Average life span(yrs)	Soil Organic carbon Increase(kg/m ² /yr)
1	Murraya paniculata (madhukamini)	711145	20	0.7
2	Oleander (Kaner Plant)	376550	20	0.7
3	Bottlebrush (Callistemon spp.)	11000	20	0.9
5	Kathal (Jackfruit, Artocarpus heterophyllus)	10800	40	1.4
6	Badam (Almond, Terminalia catarpa)	10900	30	1.3
7	Shisham, Dalbergia sisoo	8800	50	1.2
8	Morsali (Prosopis cineraria)	32000	30	0.7
9	Paras Peepal (Thespesia populnea)/ Black peepal	21200	20	0.7
10	Jungali Badam (Sterculia foetida)	5500	40	1.2
11	Tabebuia	1500	25	0.7
12	Jacaranda	2700	30	0.9

वृक्षारोपण के कारण मृदा की उर्वरकता बढ़ जाएगी



आने वाले वर्षों में रेवती रेंज में वृक्षों की घनी वानिकी के रूप में विकसित हो जाएगी

महापौर के कार्यकाल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। जिसका जीवंत उदाहरण है इंदौर के समीप स्थित पितृ पर्वत। यह पितृ पर्वत आज पूरे

देश में पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रहा है। पितृ पर्वत में आज लाखों की संख्या में पौधों का रोपण हो चुका है और सभी पौधों जीवित हैं जो एक पर्वत

के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। इस पितृ पर्वत को साकार रूप प्रदान करने का श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को ही जाता है। यहां पर लोग अपने माता-पिता या पूर्वजों की

पितृ पर्वत से 62000 कार्बन क्रेडिट के साथ भविष्य में रेवती रेंज के 51 लाख पौधारोपण से इंदौर शहर को प्राप्त होगी 12.75 लाख कार्बन क्रेडिट/वन कार्बन ऑफसेट

करीब 3 करोड़ तक की ग्रीन इनकम इंदौर शहर को विकास के लिए इस ऐतिहासिक वृक्षारोपण से मिलेगा

पितृ पर्वत एवं रेवती रेंज पर हुए व्यापक वृक्षारोपण के बाद कुल 76 लाख वृक्षों की वानिकी इंदौर शहर में स्थित रहेगी। हर वृक्ष के अलग कार्बन पृथक्करण/कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करके 12.5 लाख कार्बन क्रेडिट प्राप्त किये जा सकते हैं। पितृ पर्वत के 2.5 लाख वृक्षारोपण से ही 62000 कार्बन क्रेडिट प्राप्त हो सकेंगे।

वन कार्बन ऑफसेट/कार्बन क्रेडिट विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, जिसमें पेड़ों को फिर से लगाना, कटने के जोखिम वाले पेड़ों की रक्षा करना और कार्बन भंडारण को बढ़ाने के लिए वन प्रबंधन में सुधार करना शामिल है। परियोजनाओं का मूल्यांकन वायुमंडल से कार्बन को अलग करने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर किया जाता है। वन कार्बन क्रेडिट के जलवायु लाभ का आंकलन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बाजार संरचना के भीतर इसके मूल्य को निर्धारित करने में यह एक आवश्यक कारक है।

वानिकी से संबंधित कार्बन क्रेडिट के लिए मूल्य-आधारित निर्णय लेना महत्वपूर्ण भूमिका



याद में पौधों का रोपण करते हैं। पितृ पर्वत में लोग पितरों के नाम से एक पौधा लगाते हैं। यह क्रम वर्षों से चल रहा है। पितरों की स्मृति में यहां ढाई लाख पौधारोपण किया

गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को कई उत्कृष्ट पुरस्कारों से नवाजा जाता है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी

अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत काम किया है और कर रहे हैं। इनको भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। ताकि देश

निभाता है। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता देने वाली हितधारक योजना जैसे कि इंदौर स्थित पितृ पर्वत एवं रेवती रेंज में 53.5 लाख वृक्षारोपण कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, साथ ही सामाजिक और पारिस्थितिक लाभ में भी योगदान बनने का कारक होगा। वन कार्बन क्रेडिट का विकल्प प्रकृति संरक्षण और जलवायु के बचाव के साथ आर्थिक हित भी जुड़ा रहता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि वानिकी कार्बन क्रेडिट परियोजनाएं न केवल उत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं, बल्कि निर्धारित विशिष्ट नैतिक मानकों का भी पालन करती हो। कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं का चयन करते समय स्वतंत्र ऑडिट या गोल्ड स्टैंडर्ड या सत्यापित कार्बन स्टैंडर्ड जैसे तीसरे पक्ष के प्रमाणन जैसे सत्यापन तंत्र से होता है। ये मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पन्न क्रेडिट में वास्तविक पर्यावरणीय अखंडता हो - जिसका अर्थ है कि इनके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में शुद्ध कमी आती। भविष्य में निश्चित तौर पर रेवती रेंज पर 53.5 लाख पौधारोपण के बाद इनसे कार्बन क्रेडिट कर ग्रीन आमदनी ही हासिल की जाएगी।

SN	Species	Number of plants planted	Average carbon sequestered during lifetime in kg	Average life span(yrs)	Carbon sequestered during lifetime
1	Murraya paniculata (madhukamini)	711145	7.5	20	5333587.5
2	Oleander (Kaner Plant)	376550	11.25	20	4236187.5
3	Bottlebrush (Callistemon spp.)	11000	22.5	20	247500
5	Kathal (Jackfruit, Artocarpus heterophyllus)	10800	750	40	8100000
6	Badam (Almond, Terminalia catappa)	10900	169	30	1842100
7	Shisham, Dalbergia sissoo	8600	1875	50	16125000
8	Morsali (Prosopis cineraria)	32000	225	30	7200000
9	Paras Peepal (Thespesia populnea)/ Black peepal	21200	113	20	2395600
10	Jungali Badam (Sterculia foetida)	5500	450	40	2475000
11	Tabebuia	1500	188	25	282000
12	Jacaranda	2700	282	30	761400
13	Neem (Azadirachta indica)	5700	1500	100	8550000
14	Bixa orellana(sindur)	7800	75	20	585000
15	Casuarina	6600	393	30	2593800
17	Jaaman (Syzygium cumini)	8500	900	80	7650000
18	Tecoma (Tecoma stans or Tecoma cupensis)	5600	225	30	1260000
19	Caesalpinia pulcherrima (Gulterra)	3000	75	20	225000
20	Karanja (Pongamia pinnata)	5670	750	50	4252500
21	Terminalia	800	750	50	600000
		1235565			74714675
<p>Reference : 1. "Carbon Sequestration Potential of Urban Vegetation in Cities of Different Climate Zones" Authors:McPherson, E.G., Xiao, Q., Aguaron; Journal: Urban Forestry & Urban Greening 2. "Carbon Storage and Sequestration by Urban Trees in the USA" Authors: Nowak, D.J., Crane, D.E., Stevens, J.C. Journal: Environmental Pollution</p>					

इंदौर स्थित रेवती रेंज में कुल 1235565 पेड़ लगाकर विश्व कीर्तिमान रचा गया। भविष्य में 51 लाख पेड़ों के संकल्प के साथ 12.75 लाख कार्बन क्रेडिट इन वृक्षारोपण के कारण मिलेगा

के कई अन्य लोग भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित हो। हम मानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की साधना और तपस्या ही है जो इनको राजनीतिक जीवन में भी

पर्यावरण के प्रति प्रेम का भाव जागृत किये हुए है। सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि देश के किसी हिस्से में ये पौधारोपण का अवसर प्राप्त होता है वह वहां भी पौधारोपण कर

पर्यावरण संवर्धन का संदेश प्रसारित करते हैं। पर्यावरण के प्रति इनका यह स्नेह और संकल्प हमें प्रेरणा देता है कि सबको अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधों का रोपण

बंजर था पितृ पर्वत, पूर्वजों की याद में लगावाए ढाई लाख पौधे

पितृ पर्वत



एक समय बंजर पहाड़ हुआ करता था पितृ पर्वत। नगर निगम इंदौर ने इस पहाड़ पर पंप हाउस बनाकर रखा था। पूरा पहाड़ बंजर था। कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने पूर्वजों की याद में पितृ पर्वत पर पेड़ लगाएं। इस तरह दो दशकों में लगभग यहां ढाई लाख पौधे लगाए गए जो वृक्ष बन चुके हैं। इसके पूर्व 2002 से ही इंदौर में पौधारोपण को लेकर विशेष पहल शुरू हो चुकी थी। तत्कालीन महापौर के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने एक वृहद् पौधारोपण योजना बनाई थी। इसके अंतर्गत इंदौर हवाईअड्डे से मात्र तीन किमी की दूरी पर स्थित धरम टेकरी नामक स्थान को चिन्हित किया गया था। यहां वृहद् स्तर पर पौधारोपण किया गया और जनता को भी प्रेरित किया गया कि यहां पर अपने पूर्वजों की स्मृति में पौधारोपण करें। इसी से जोड़ते हुए इस स्थान का नाम परिवर्तित कर पितृ पर्वत कर दिया गया। आम लोगों के साथ ही विशिष्टजन भी यहां अपने पूर्वजों के नाम से पौधारोपण करते हैं। अब तक यहां लाखों पेड़ लगाए जा चुके हैं।

करना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। पर्यावरण नहीं तो हम नहीं। आज देश को विजयवर्गीय जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता

है जो एक ऐसे संकल्प को साकार कर रहे हैं जिसकी जरूरत सबको है।
मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर

अपने नवाचारों के लिये प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में विशेष स्थान रखता है। फिर बात चाहे स्वच्छता के क्षेत्र में अक्वल होने की हो

इंदौर में 51 लाख पौधारोपण के बाद भविष्य में 5-6 डिग्री तापमान शहर का कम हो जाएगा : कैलाश विजयवर्गीय

पहले इंदौर में तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस रहता था। मालवा में तापमान कभी 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होता था, लेकिन अब यह 48 डिग्री तक पहुंच गया है, यह बड़ी समस्या है। मैंने तभी संकल्प लिया था और कहा था कि पांच साल में तापमान पांच डिग्री कम करना है। हमने 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। इंदौर में हर साल 51 लाख पेड़ लगाने के बाद इंदौर का तापमान पांच डिग्री कम हो जाएगा। यह संकल्प



संतों और आम लोगों के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। इस बार मालवा में पड़ी 47-48 डिग्री की भीषण गर्मी ने उन्हें इस संकल्प के लिए और प्रतिबद्ध कर दिया। बस, फिर क्या था, ये इंदौर है। नित्य नूतन करने को सदैव तत्पर। जैसे इस शहर के बाशिंदों ने स्वच्छता अभियान में देश में अहिल्या नगरी इंदौर का नाम अव्वल किया, वैसे ही ये शहर हरियाली के इस अनुष्ठान में जुट गया। 46 दिन पहले इस अभियान की संकल्पना ने आकार लिया और देखते ही देखते न केवल इंदौर, बल्कि पूरे अंचल व प्रदेश में इंदौर के एक पेड़ मां के नाम अभियान का डंका बज गया। 51 लाख पौधे रोपने के इस अभियान में शहर का हर समाज, वर्ग, संस्था, संगठन आगे आ गए। देश के अन्य हिस्सों ने भी मदद का हाथ आगे कर दिया। 20 करोड़ रुपए के पौधे तो इस संकल्प को दान में ही मिल गए। आज इंदौर ने 11 लाख पौधारोपण कर विश्व कीर्तिमान रचा है।

या फिर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिये गये कार्यों की। इंदौर शहर व वहां के लोग लगातार विशिष्ट कार्यों से अपनी पहचान

को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। जब बात की शहर की उपलब्धियों की होती है तो उसमें जितना योगदान वहां की स्थानीय

जनता का है उतना ही महत्वपूर्ण योगदान वहां के जनप्रतिनिधि का होता है। यही कारण है कि इंदौर के जनप्रतिनिधि और

राजनीतिक जीवन में अभी तक अपराजेय रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय

2023 में मध्यप्रदेश में अपनी दम पर 90 सीटें जीता भाजपा सरकार बनवाना, पहली बार हरियाणा में कमल खिलवाना, पश्चिम बंगाल में 03 से 77 सीटें पार्टी को जिताकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी संगठनात्मक शक्ति साबित की है। आज कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे योद्धा बन गए हैं जो कभी पराजित नहीं हुए है। पहली बार कांग्रेस के गढ़ में पार्षद बनना, फिर महापौर चुनाव जीतना, महापौर रहते मालवा और



इंदौर से चुनाव जितवाकर विधायक बनना और भाजपा की 10 साल बाद सरकार बनवाना हो। 11 साल मंत्री रहने के बाद राष्ट्रीय संगठन में दायित्व संभालकर हरियाणा में पहली बार कमल खिलवाना। वामपंथ, ममता और हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा कैडर खड़ा करके 03 से 77 सीटों पर पार्टी को पहुंचाना या इसके बाद मध्यप्रदेश चुनावों में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जनता के गुस्से के बावजूद प्रदेश स्तर पर 103 सीटों का दायित्व निभाकर उसमें से 90 सीटें जिताकर भाजपा सरकार बनवाना शायद यह काम कोई जादूगर ही कर सकता है। कहने में गुरेज नहीं कि राजनीतिक युद्ध में अभी तक कैलाश विजयवर्गीय अपराजित योद्धा रहे हैं।

अपनी मेहनत से मध्यप्रदेश में बाजी पलट दी थी कैलाश विजयवर्गीय ने

कोई पार्टी या संगठन किसी भी राज्य में तभी सरकार बनाने में कामयाब होता है जब उस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें। सभी पूरी एकाग्रता के साथ क्षेत्र और नगर में विकास की नींव रखें और उसे पूरा करने में निरंतर जुटे रहे। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले से मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसी ही सक्रियता प्रदेश चुनावों में दिखलाई थी। इंदौर की सभी विधानसभा सीटों में भाजपा ने जो क्लीन स्वीप किया था वह इस बात का प्रमाण है कि इंदौर जिले में विजयवर्गीय की लोकप्रियता आज भी वैसी ही है, जैसे पहले थी। विजयवर्गीय की 103 सभाओं में 95 प्रतिशत में जीत हुई। वे इंदौर में सभी सीटें जितवाने में कामयाब रहे। विजयवर्गीय को इंदौर -1 से कांग्रेस के

लोकप्रिय नेता होने के कारण प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की जनता के साथ मिलकर निरंतर

पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन की दिशा में नित नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। महापौर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक और राज्य कैबिनेट

में शामिल होने के सफर पर आगे बढ़ते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कभी भी इंदौर की जनता का साथ नहीं छोड़ा। सिर्फ साथ ही



संजय शुक्ला के सामने उतारा गया। यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। लेकिन पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेस के इस किले को भेदने की जिम्मेदारी दी। जिसे भेदने में वह कामयाब भी रहे। इसके साथ ही पूरे इंदौर की सीटों पर भी बीजेपी का परचम लहराया। युवावस्था से लेकर अब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की एक-एक गली को अच्छी तरह से जाना और पहचाना। यही नहीं लोगों के बीच जिस विश्वास के साथ जुड़ाव के लिये पहुंचे लोगों ने उन्हें उतना ही मान-सम्मान और अपनापन दिया। यही कारण है कि आज वे लोकप्रिय नेता बन गये हैं। बताया जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय वह नेता हैं जो लोगों के मन में बसते हैं। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव का टिकट मिलते ही लोगों ने उन्हें विजेता मान लिया था और उन्हें कार्यकर्ताओं ने आश्वस्त भी कर दिया था कि इस सीट से उन्हें



नहीं बल्कि उन्होंने इंदौर के विकास और प्रगति के लिये लगातार प्रयास किये हैं जिसका परिणाम है कि आज इंदौर देश में

मुंबई के बाद प्रमुख व्यापारिक शहरों की सूची में आता है। अब बात अगर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की करें तो इंदौर को

स्वच्छता में प्रथम शहर का तमगा दिलाने में भी कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका मुख्य रही है। उन्होंने वहां की जनता के साथ



जनता का अपार स्नेह मिलेगा। जनता के बीच प्रेम और स्नेह का जो भाव आज कैलाश विजयवर्गीय में दिखता है वह आज का ही नहीं है। इसकी नींव तो कैलाश विजयवर्गीय ने लगभग चार दशक पहले रख दी थी जब वे प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए। उन्होंने पूरी सक्रियता के साथ जिले के विकास, युवाओं के रोजगार, स्व-रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की नींव रखी और धीरे-धीरे इंदौर को वह सब कुछ दिलवाया जिसके लिये इंदौर और वहां के लोग हकदार थे। इंदौर का महापौर रहते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने शहर में स्वच्छता के लिये लोगों को प्रेरित किया और जागरूक करते हुए स्वच्छता को अपनाने का आह्वान किया। छात्र राजनीति से लेकर, पहले संगठन, फिर पार्टी और कैबिनेट मंत्री के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने जो कार्य किये हैं वह आज जनता के सामने हैं। यही कारण है कि इंदौर में न सिर्फ वह खुद बल्कि अन्य सीटों पर भी उन्होंने भाजपा को सफलता दिलवाई। आज इंदौर बिजनेस हब बन गया है, इसे मिनी मुंबई का ताज मिला है। देश में स्वच्छ शहर होने का जो गौरव इंदौर को मिला है वह जनता की सक्रियता, राजनेताओं के प्रोत्साहन और सरकार के सहयोग से संभव हुआ है।

प्रदेश के बाहर भी दिखाई संगठनात्मक शक्ति

अगर हम कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकुशलता की बात करते हैं तो इस बात का जिक्र करना आवश्यक होगा कि वह विजयवर्गीय ही हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में ममता बैनर्जी के किले को भेदने का साहस दिखाया और भाजपा पार्टी ने भी उन पर भरोसा कर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। इसके साथ ही इससे पहले उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था। वहां भी उन्होंने पार्टी को खड़ा कर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। मध्यप्रदेश की राजनीति से बाहर निकलकर जब कैलाश विजयवर्गीय संगठन में कार्य करने पहुंचे तो उन्होंने कई प्रमुख कार्य किये और सत्ता के बाहर संगठन में अपनी विशेष पहचान बनाई है।

मिलकर स्वच्छता को एक जनआंदोलन बनाया और जब यह आंदोलन पूरे देश में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुका उसके

बाद वे रूके नहीं और निरंतर आगे बढ़ते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण

को जनांदोलन बनाते हुए देश की जनता से एक पौधा अपनी मां के नाम से रोपने का आह्वान किया है। इस आंदोलन को

कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में रचा गया विश्व कीर्तिमान 12 घंटे 11 लाख पौधों का हुआ रेवती रेंज में पौधारोपण



रेवती रेंज इंदौर की विशाल पहाड़ी पर 12 लाख 41 हजार के पौधारोपण का विश्व रिकार्ड गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बुक में दर्ज

पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया। इंदौर के रेवती रेंज विशाल पहाड़ी पर एक दिन में 11 लाख पौधे रोपकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है। यह कीर्तिमान कैलाश विजयवर्गीय के प्रयासों से संभव हुआ है। इस उपलब्धि के लिए कैलाश विजयवर्गीय को कई सम्मानों से नवाजा गया है।

अमली जामा पहनाते हुए 14 जुलाई को इंदौर में 12 घंटे से भी कम समय में 11 लाख पौधे रोपे गए, जिसे गिनीज रिकॉर्ड

द्वारा एक विश्व कीर्तिमान घोषित किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय द्वारा शहर में 51 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में पौधारोपण किया। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रेवती रेंज में



प्रधान मंत्री
Prime Minister

संदेश

मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण महाअभियान के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। स्वच्छता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने से इस महाअभियान की शुरुआत 'क्लीन' के साथ 'ग्रीन' होने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह देखना सुखद है कि हाल ही में की गई 'एक पेड़ माँ के नाम' लगाने की अपील को देशवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हरित धरा बनाने की मुहिम में मध्य प्रदेश की जनता जिस उत्साह से आगे बढ़ रही है वह सराहनीय है। एक भव्य व विकसित भारत की ओर अग्रसर राष्ट्र के सामूहिक प्रयास हरित युग का निर्माण कर रहे हैं।

वृक्षारोपण महाअभियान को समाज के विभिन्न वर्गों की महान विभूतियों से जोड़ने के विचार और इसकी सफलता के लिए व्यापक रणनीति से लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। जन-जन की भागीदारी बढ़ाने के लिए विविध गतिविधियों के आयोजन और दुनियाभर के भारतबंधियों को मुहिम का हिस्सा बनाने की पहल के बारे में जानकर खुशी हुई है।

देश आज प्रकृति की रक्षा के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मुझे विश्वास है कि वृक्षारोपण महाअभियान से देश व समाज में पर्यावरण की बेहतरी के लिए योगदान देने की भावना को जल मिलेगा और एक हरित व स्वस्थ भारत का हमारा संकल्प सिद्ध होगा।

वृक्षारोपण महाअभियान से जुड़े सभी लोगों को भविष्य के प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली

आषाढ़ 14, शक संवत् 1946

05 जुलाई, 2024

प्रधानमंत्री के सपने को कैलाश विजयवर्गीय के संकल्प ने किया पूरा, एक पेड़ माँ के नाम मुहिम से 51 लाख पौधे रेवती रेंज में रोपे गये।

पीपल का पेड़ लगाया है।

धर्म हरेक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विषय होता है, उसी प्रकार भक्ति भी। ऐसी ही भक्ति भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की 'पित्रेश्वर हनुमान धाम' को लेकर नजर आती है। पित्रेश्वर हनुमान धाम, पितृ पर्वत इंदौर में स्वयं कैलाश विजयवर्गीय ने निर्माण करवाया है। इंदौर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित पितरेश्वर हनुमान भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। यहां हनुमान जी अपने वृहद आकार में ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं। साथ ही भगवान श्रीराम की भक्ति कर रहे हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी अष्ट धातु की प्रतिमा है। पितरेश्वर हनुमान मूर्ति को लगवाने से लेकर प्राण-प्रतिष्ठा तक का श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को जाता है। उन्होंने शहर के लोगों से आग्रह किया कि वे पितृ पर्वत पर अपने पितरों के नाम से एक पौधा लगाएं। इसकी शुरुआत हुई तो 22 सालों में लोगों ने पितृ पर्वत पर हजारों पौधे रोपे। साथ ही लोगों ने करीब-करीब तीन लाख पौधे अपने पितरों का स्मरण करते हुए लगवाया है। कैलाश विजयवर्गीय को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार मिलना चाहिए।

कैलाश विजयवर्गीय ने लिया था अन्न त्यागने का फैसला

मुझे याद आता है कि लगभग 22 वर्ष पहले जब कैलाश विजयवर्गीय ने पितृ पर्वत पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना का संकल्प लिया था। उसी समय उन्होंने अन्न त्यागने का फैसला किया था। वे लगभग 20 वर्षों तक अपने इस फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने लगभग दो दशकों तक मुंह में अन्न का दाना तक नहीं रखा। अपनी प्रतिज्ञा पर काबिज रहते हुए विजयवर्गीय ने वर्ष 2020 में विशेष अनुष्ठान-अर्चना कर अन्न ग्रहण किया।

2014-2020 तक तकरीबन 2000 करोड़ रुपये खर्च करके भी सिर्फ बच पाये 10 फीसदी पौधे

शिवराज शासनकाल में वृक्षारोपण का महज हुआ था दिखावा

प्रदेश को हरा-भरा रखने हर साल चार से पांच करोड़ पौधे लगाए जाते हैं। इन पौधों की खरीदी और रखरखाव पर तकरीबन 400 करोड़ तक का खर्च आता है। पिछले पांच साल में वन विभाग ने 20 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे। देखा जाता है कि लगाए गए पौधों में से कितने फीसदी जीवित बचे, लेकिन पौधारोपण के बाद की गणना और मानीटरिंग का रिकार्ड मौजूद नहीं है, वन



अधिकारी दावा जरूर कर रहे हैं कि लगाए गए पौधों में से 50 फीसदी से ज्यादा जीवित हैं, लेकिन मैदानी हकीकत कुछ और है। मप्र में वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक 1638 करोड़ रु. में 20 करोड़ 92 लाख 99 हजार 843 पौधे लगाए गए। यानी एक पौधा लगाने और उसके रखरखाव पर करीब 78 रूपए खर्च हुए। छह साल में से ज्यादातर का बड़ा हो जाना भी तय है, लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की रिपोर्ट कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। छह साल में प्रदेश में 100 वर्ग किमी से अधिक का वन क्षेत्र कम हुआ है। इतना ही नहीं, मप्र में एक जनवरी 2015 से 5 फरवरी 2019 तक 12 हजार 785 हेक्टेयर वन भूमि दूसरे कामों के लिए दे दी गई। 2005 के मुकाबले 2019 में ग्रीन कवर 1469 वर्ग किमी बढ़ा है। जानकारों की मानें तो सागौन के एक पौधे को नर्सरी में तैयार करने से लेकर प्लांटेशन तक 18 से 20 रूपए खर्च होते हैं। हर साल उसके रखरखाव पर डेढ़ से दो रूपए का खर्च होता है। एक हेक्टेयर पर प्लांटेशन है तो दो हजार रूपए खर्च आता है। जबकि विभाग प्रति पौधे 78 रु. खर्च बता रहा है यानी तीन से चार गुना ज्यादा। सरकार ने 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक कुल तीन करोड़ 57 लाख 33 हजार 524 पौधे खरीदे। शिवराज सरकार में पौधारोपण पर 362 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। साल 2021-22 में अकेले पौधारोपण पर 350.96 करोड़ रूपए खर्च हुए। वहीं इनके संरक्षण पर भी सरकार ने 17.98 करोड़ रूपए खर्च कर डाले। इसी तरह साल 2020-21 में पौधारोपण पर 348 करोड़ और संरक्षण पर 20.92 करोड़ रूपए

कैलाश विजयवर्गीय सन 2000 में जब इंदौर के महापौर बने उस समय उन्हें किसी संत ने बताया था कि शहर पितृ दोष से ग्रस्त

है और इसी वजह से इंदौर का विकास अवरूद्ध है। इसके उपाय के तौर पर यह बताया गया कि अगर इंदौर के पितृ पर्वत पर

भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाए तो यह दोष दूर हो सकता है। भाजपा कैलाश विजयवर्गीय ने अपने जन्म

खर्च हुए थे। विधानसभा में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक कुल तीन करोड़ 57 लाख 33 हजार 524 पौधे खरीदे। जिसे खरीदने में मध्य प्रदेश सरकार को 328 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करनी पड़ी। जबकि इनके रख रखाव पर सरकार का 34 करोड़ से अधिक का खर्च आया। इन आंकड़ों के मुताबिक एक पौधा खरीदने के लिए सरकार ने 92 रुपए खर्च किया। जबकि रखरखाव में प्रति पौधा सरकार को 9.60 रुपए का खर्च आया।

बीते पांच सालों में पौधारोपण में आई गिरावट

बीते पांच वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार को एक पौधा खरीदने के लिए 36 रुपए अधिक खर्च करने पड़े। 2016-17 में सरकार को एक पौधा खरीदने के लिए 56.64 रुपए खर्च करने पड़ते थे जो अब बढ़कर 92 रूपये से उपर पहुंच गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक पौधों के दाम में करीब 62.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि बीते पांच सालों में पौधारोपण में काफी गिरावट आयी है। 2016-17 और साल 2017-18 में सरकार ने क्रमशः पांच करोड़ और 06 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण किया। लेकिन 2022 आते आते यह 5-6 करोड़ से घटकर साढ़े तीन करोड़ पर आ गया। सरकार ने सबसे अधिक पौधे वर्ष 2017-18 में खरीदे थे तब मध्य प्रदेश सरकार ने 06 करोड़ 05 लाख से



ऊपर पौधे खरीदे जिस पर प्रदेश सरकार को 393 खर्च करने पड़े थे। इनके रख रखाव में 127 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। उस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार को एक पौधा 65 रुपए में पड़ा था। प्रदेश सरकार ने इस आधार पर गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश की थी। लेकिन नर्मदा किनारे वृक्षारोपण के दावों की पोल दिग्विजय सिंह की पैदल नर्मदा परिक्रमा में खुल गयी। किनारों पर पौधारोपण का कोई नामोनिशान न होने के सिंह के दावे पर सरकार सफाई देने पर आ गयी थी।

शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण पर पांच साल में खर्च किये 2000 करोड़ रुपये, नतीजा रहा सिफर

हर दिन एक पौधा लगाने का रिकार्ड बना चुके सीएम शिवराज के राज में पौधारोपण पर पांच साल में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि अब तक इस प्लान्टेशन के बाद दस फीसदी पौधे ही बच पाए हैं। खास बात ये है कि सीएम शिवराज अपने हाथों से जो पौधा लगाते हैं उनमें 98 फीसदी पौधे भोपाल की स्मार्ट सिटी में ही लगाए गए हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में जिसमें खासतौर पर नर्मदा किनारे किए गए पौधारोपण का ये हाल है कि पौधे ही नहीं बचे। 2000 करोड़ खर्च करने के भी दस फीसदी ही बढ़ पाया है। एमपी सरकार ने मार्च में पौधारोपण को लेकर विधानसभा में रिपोर्ट पेश की, यह रिपोर्ट सरकार द्वारा कराए गए पौधारोपण की स्थिति को बताती है। पौधारोपण की स्थिति पर विधायक डॉ. हीरालाल अलावा ने सवाल पूछा था इस सवाल के जवाब में सरकार ने

स्थान इंदौर की उन्नति के लिए संकल्प लिया कि वह जब तक पितृ पर्वत पर विश्व की सबसे उंची अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित

नहीं कराएंगे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। 20 साल बाद जाकर उनका यह संकल्प पूरा हुआ।

इंदौर के पितृ पर्वत पर 72 फीट उंची, 108 टन वजन की अष्टधातु की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा

पौधारोपण की स्थिति बताई थी। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक सरकार ने पौधारोपण पर 02 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इतनी राशि खर्च करने के बाद मात्र 10 फीसदी का फॉरेस्ट बढ़ सका है। प्रदेश के वनों को हरा रखने और पौधारोपण के बाद उनके संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने बीते चार साल में 16 सौ करोड़ रुपए खर्च कर डाले। पौधारोपण पर बीते चार साल में 1510 करोड़ खर्च किए गए। इनके रखरखाव पर करीब 90 करोड़ खर्च हुए। इतना खर्च करने के बाद भी हरियाली भी नहीं बढ़ी और अवैध कटाई भी नहीं रुक पाई।

932 वर्ग किलोमीटर का मध्यम घना जंगल घटा: सरकार की ओर से विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2016 से 2021-22 तक पौधारोपण पर 02 हजार करोड़ खर्च किए हैं। इसके बाद भी मध्यम घना जंगल 132 वर्ग किमी तक घट गया है। वर्ष 2019 में मध्यम घना जंगल 34,341 वर्ग किमी था, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 34,209 रह गया। इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश के जंगलों में जमकर अवैध

कटाई हो रही है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वन मंत्री उमंग सिंघार ने पौधारोपण में होने वाली धांधली को रोकने एक सर्वे कराया था, उस सर्वे में पौधारोपण की हकीकत सामने आई थी। विभाग ने बैतूल उत्तर मंडल की शाहपुरा रेंज में 15 हजार 526 पौधे लगाने का दावा किया, लेकिन मौके पर नौ हजार गड्डे ही मिले थे। इनमें भी दो से ढाई हजार पौधे ही पाए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2009 में 07 लाख 47 हजार, वर्ष 2010 में 06 लाख 60 हजार और वर्ष 2011 में 07 लाख 04 हजार पौधे रोपे गए।



साल 2020-21 में वन विभाग ने 3 करोड़ 86 लाख से ज्यादा और साल 2021-22 में 03 करोड़ 02 लाख से ज्यादा पौधे लगाए।

हर साल करोड़ों पौधों लग रहे लेकिन घट रहा जंगल क्षेत्र

मध्य प्रदेश के जंगलों को हरा-भरा रखने के लिए हर साल पौधे लगाए जाते हैं। इन पौधों की खरीद और रख-रखाव पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। मप्र सरकार द्वारा पौधारोपण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बाद भी जंगल घट रहा है। वर्ष 2019-20 में मध्यम घना जंगल 34341 वर्ग किमी था, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 34209 वर्ग किमी रह गया। यही नहीं, बहुत घने जंगल का रकबा भी दो किमी घटा ही है। वर्ष 2019-20 में ये आंकड़ा 6667 वर्ग किमी था, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 6665 वर्ग किमी पर आ गया। दूसरी तरफ, वर्ष 2019 में ओपन फॉरेस्ट का दायरा 36,465 वर्ग किमी था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 36,618 वर्ग किमी हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ओपन फॉरेस्ट का दायरा 153 वर्ग किमी तक बढ़ गया है। अति सघन वन वह होते हैं, जिनमें वृक्षों का घनत्व 70 फीसदी से ज्यादा है। सघन वन में पेड़ों का घनत्व 40 से 70 फीसदी तक होता है। ओपन या खुले वनों में पेड़ों का घनत्व 10 से 40 फीसदी तक होता है।

की गई। इस पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के

पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, संत मुरारी बापू और वृंदावन से महामंडलेश्वर गुरु शरणानंदजी महाराज की

उपस्थित में कैलाश विजवर्गीय ने 20 साल बाद संकल्प पूरा होने पर अन्न ग्रहण किया। इतना ही नहीं इन 20 वर्षों में कैलाश

सरल और सहज कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक जीवन



कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक और सामाजिक जीवन सरल और सहज है। उन्होंने समाजसेवा के साथ समाज से सरोकार रखने वाले मुद्दों को भी प्राथमिकता में रखते हैं। उनका संपूर्ण जीवन विवादमुक्त रहा है। राजनीति जीवन में वह कई अहम पदों पर रहे हैं। लेकिन उनका जीवन बेदाग रहा है। उन्होंने राजनीति की शुरूआत इंदौर से ही की है। इंदौर महापौर रहते उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं। महापौरों के विश्व सम्मेलन में होनोलूलू, अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ महापौर के रूप में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें चीन में आयोजित विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन की प्रिपरेटरी कमेटी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें 2003 में दक्षिण एशिया के महापौर परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था और

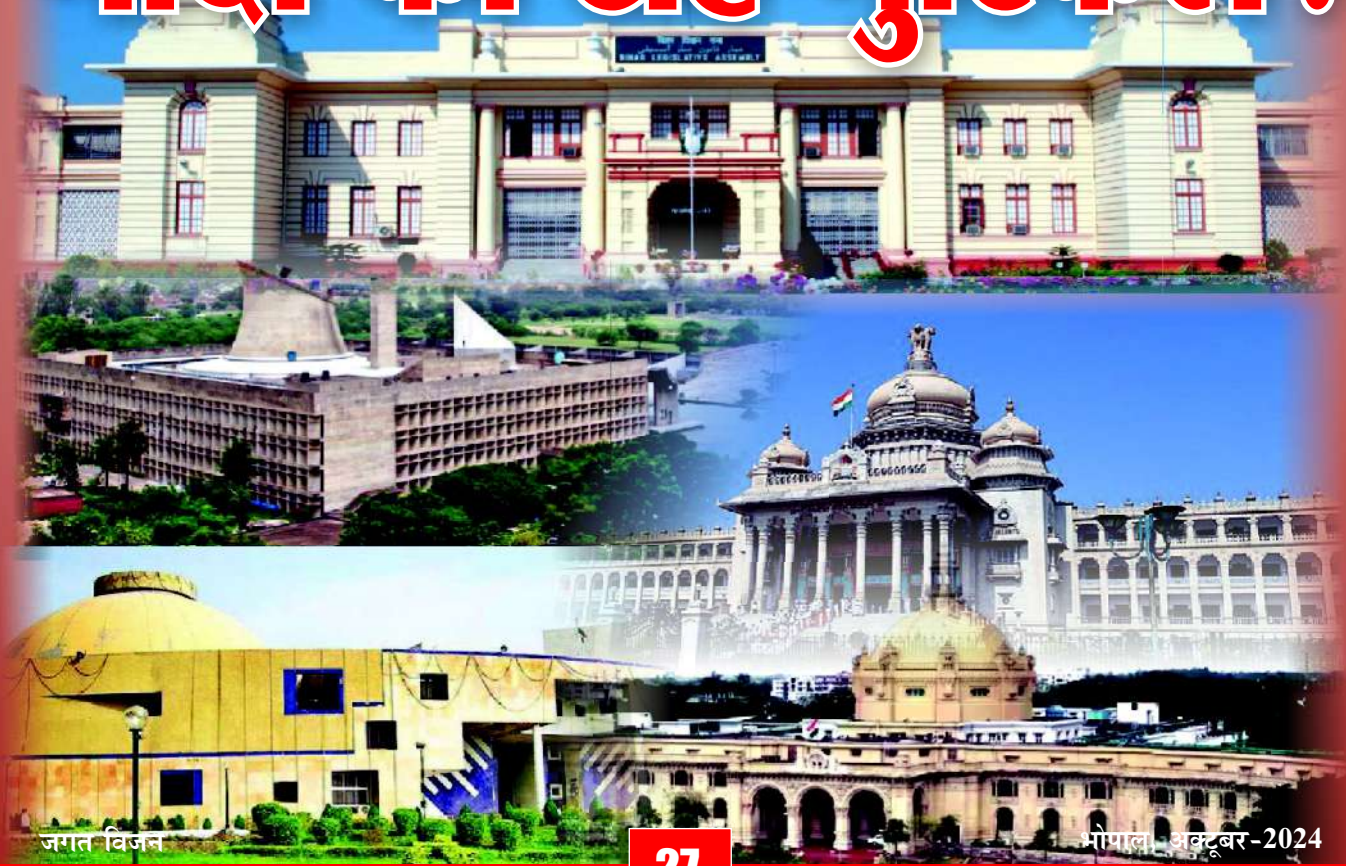
उन्होंने डरबन में विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भारतीय स्वैच्छिक संगठन की टीम का नेतृत्व किया था। यह श्रेय इंदौर में पर्यावरण सुधार और ग्रीन लिविंग के प्रति उनके समर्पित प्रयासों को दिया जाता है कि इंदौर को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ शहर, ग्रीन सिटी 2002 से सम्मानित किया गया था। उनकी असीमित शांति विजय और प्रयासों के लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुडविल पुरस्कार मिला, इसके साथ कैलाश विजयवर्गीय के प्रयासों के कारण उद्योग निर्माण नेतृत्व पुरस्कार भी मिला और आईटी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट उत्पादन के कारण राज्य को तीन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

विजयवर्गीय ने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने पूर्वजों की याद में पितृ पर्वत पर पेड़ लगाएं। इस तरह दो दशकों में लगभग यहां

ढाई लाख पौधे लगाए गए, जो वृक्ष बन चुके हैं। अपने शहर को एक दोष मुक्त शहर से उबारकर विकसित शहर बनाने की दिशा में

अनेकों पहल करने वाले कैलाश विजयवर्गीय का कार्य सचमुच प्रशंसनीय और पुरस्कृत करने योग्य है।

वन नेशन-वन इलेक्शन मोदी की राह मुश्किल !



अभी हाल ही में मोदी सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसे लागू करने के लिए सरकार को एक नहीं, बल्कि दो-दो संविधान संशोधन विधेयकों को पास कराना होगा, जिसके तहत संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। खैर, कोविंद कमिटी की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब आगे क्या? 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लागू करने के लिए सरकार का आखिर प्लान क्या है? कैसे लागू होगा? ये सभी सवाल अभी भी सामने खड़े हैं। कोविंद पैनल की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है उससे लगता है कि इसे निकट भविष्य लागू कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में घिरा हुआ नजर आता है।

विजया पाठक

लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। अभी हाल ही में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराये जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिये तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ राजनीतिक दलों ने इस

विचार से सहमति जताई, जबकि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि यह विचार लोकतांत्रिक

प्रक्रिया के खिलाफ है। जाहिर है कि जब तक इस विचार पर आम राय नहीं बनती तब तक इसे धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा।

अभी हाल ही में मोदी सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसे लागू करने के लिए सरकार को एक नहीं, बल्कि दो-दो संविधान संशोधन विधेयकों को पास कराना होगा, जिसके तहत संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। खैर, कोविंद कमिटी की रिपोर्ट को

देश के हित में एक
देश-एक चुनाव
सभी को करना
चाहिए समर्थन



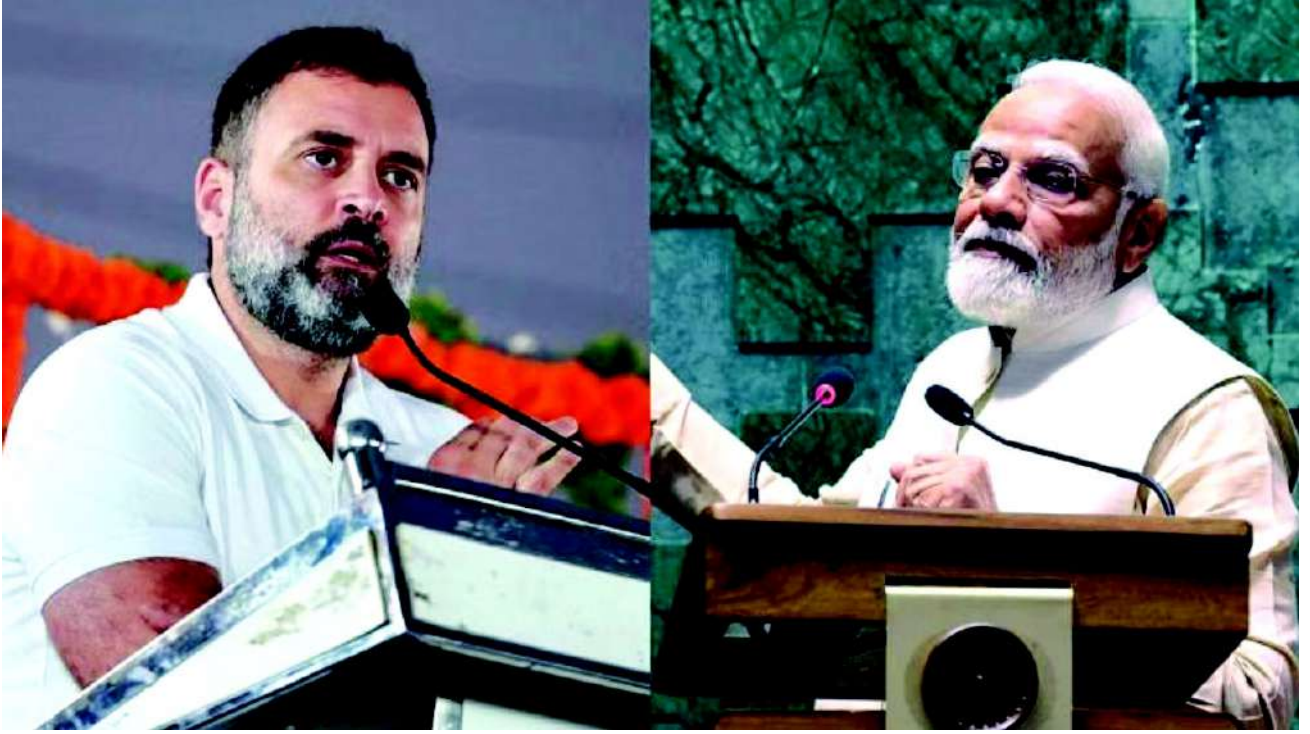
यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो निश्चित ही यह देश के हित में होगा। विपक्षी पार्टियों को भी इसका समर्थन करना चाहिए।

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब आगे क्या? 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लागू करने के लिए सरकार का आखिर प्लान क्या है? कैसे लागू होगा? ये सभी सवाल अभी भी सामने खड़े हैं। कोविंद पैनल की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा।

राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है उससे लगता है कि इसे निकट भविष्य लागू कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में घिरा हुआ नजर आता है।

कैसे लागू करने का है प्लान

सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद दूसरे चरण में पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगी।



भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा। केंद्र पूरे देश में इस बारे में विस्तृत चर्चा शुरू करेगा। पैनल की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा।

कोविंद पैनल की सिफारिशों में क्या-क्या ?

कोविंद पैनल के मुताबिक जब संसद का सत्र होगा, तो इस कदम को अधिसूचित करने के लिए एक तारीख तय की जानी चाहिए। उस नियत तिथि के बाद होने वाले राज्य चुनावों से बनने वाली सभी विधानसभाएं केवल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक की अवधि के लिए ही होंगी। इसका मतलब है कि बदलाव के लिए लोकसभा चुनाव के बाद एक तारीख तय की जाएगी। उस तारीख के बाद जिन राज्यों में चुनाव होंगे, उनका कार्यकाल आम चुनावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए

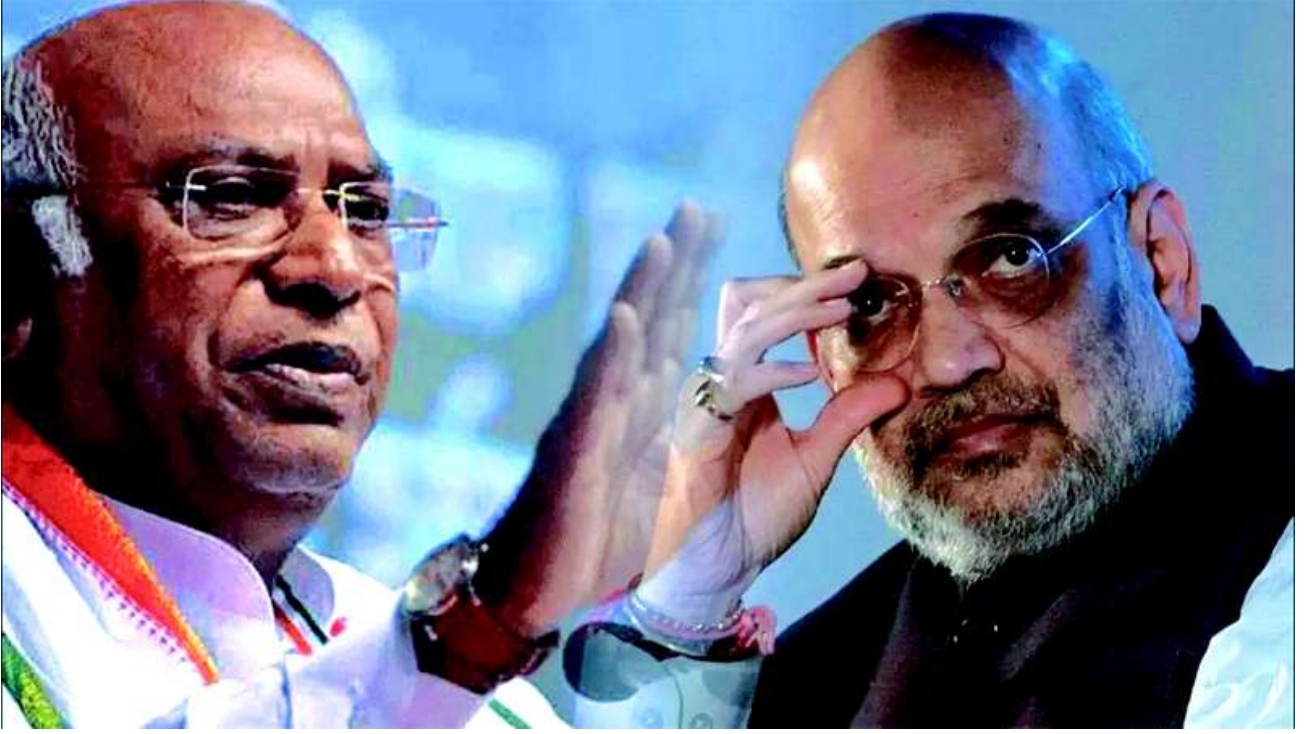
कम कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 2024 और 2028 के बीच बनने वाली राज्य सरकारों का कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनावों तक ही होगा। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अपने

बदलाव के लिए लोकसभा चुनाव के बाद एक तारीख तय की जाएगी। उस तारीख के बाद जिन राज्यों में चुनाव होंगे, उनका कार्यकाल आम चुनावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कम कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 2024 और 2028 के बीच बनने वाली राज्य सरकारों का कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनावों तक ही होगा।

आप एक साथ होंगे।

कहीं विपक्ष तो नहीं बनेगा अड़चन ?

मिसाल के तौर पर, एक राज्य जहां 2025 में चुनाव होना है, उसके पास चार साल के कार्यकाल वाली सरकार होगी जबकि 2027 में चुनाव कराने वाले राज्य में 2029 तक केवल दो साल के लिए सरकार होगी। जैसे बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं तो वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करने के लिए उसकी विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक रहेगा यानी सिर्फ 04 साल का। इसी तरह 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उसके बाद बनने वाली सरकार सिर्फ 02 साल रहेगी। ऐसे ही अन्य राज्यों के मामले में भी होगा। फिर 2029 में लोकसभा के साथ-साथ सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव भी मुमकिन हो सकेगा। कोविंद पैनल की सिफारिशों को माने तो 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए कम से कम



18 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी। इनमें से ज्यादातर संविधान संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं के समर्थन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन, इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी जिन्हें संसद द्वारा पारित करना होगा।

क्यों है जरूरत एक देश एक चुनाव की

किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित

होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। इस सबसे बचने के लिये नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया।

एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएँ विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई।

एक राष्ट्र, एक चुनाव की पृष्ठभूमि क्या है?

एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएँ विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब करवाने में क्या समस्या है। एक तरफ जहाँ कुछ जानकारों का मानना है कि अब देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा एक साथ चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक कहते हैं कि अगर देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीक और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है। इसलिए

एक देश एक चुनाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु इन सबसे इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती, इसके लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष में दिये गए तर्कों का विश्लेषण करना होगा।

एक देश एक चुनाव का समर्थन क्यों?

एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा

समस्या आती है। इसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनावों की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिये बनाया गया है। इसके तहत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद सत्ताधारी दल के द्वारा किसी परियोजना की घोषणा, नई स्कीमों

का चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी और इसके बाद विकास कार्यों को निर्बाध पूरा किया जा सकेगा। एक देश एक चुनाव के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि इससे बार-बार चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। गौरतलब है कि बार-बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त



**ONE NATION
ONE ELECTION**



जाता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है लगातार चुनावों के कारण देश में बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने

की शुरुआत या वित्तीय मंजूरी और नियुक्ति प्रक्रिया की मनाही रहती है। इसके पीछे निहित उद्देश्य यह है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में अतिरिक्त लाभ न मिल सके। इसलिए यदि देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं

आर्थिक बोझ पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की आर्थिक सेहत के लिये ठीक नहीं है। इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि चुनावों के

खतरे में होगा क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व?



एक देश एक चुनाव का विरोध करने का एक कारण यह भी हो सकता है कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। शायद इसी वजह से इस बदलाव का विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये पार्टियां नहीं चाहती कि यह व्यवस्था देश में लागू हो। निश्चित ही इसकी तस्वीर आने वाले समय में साफ होगी। फिलहाल तो अभी इसमें काफी अड़चने दिखाई पड़ रही है।

दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। एक साथ चुनाव कराने से सरकारी

कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार-बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय तो बचेगा ही

और वे अपने कर्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पायेंगे।

एक देश एक चुनाव का विरोध क्यों ?



रामनाथ कोविंद ने एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में वह सम्पूर्ण जानकारीयां है। चुनाव कैसे और कब कराये जा सकते हैं।

यह विचार देश के संघीय ढाँचे के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिये घातक कदम होगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं के मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जायेगा जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएँ या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो दें। कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव

संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएँ या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो दें। कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे छोटे-छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है।

जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे छोटे-छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराये जाते हैं, तो ऐसा होने की आशंका बढ़ जाएगी।

क्या है वन नेशन-वन इलेक्शन पर बनी समिति की रिपोर्ट?

रिपोर्ट में आने वाले वक्त में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ-साथ नगरपालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने के मुद्दे से जुड़ी सिफारिशें दी गई हैं। 191 दिनों में तैयार इस 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 राजनीतिक



दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए थे जिनमें से 32 राजनीतिक दल 'वन नेशन वन इलेक्शन' के समर्थन में थे। रिपोर्ट में कहा गया है, 'केवल 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर शेष 32 दलों ने न केवल साथ-साथ चुनाव प्रणाली का समर्थन किया बल्कि सीमित संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए ये विकल्प अपनाने की जोरदार वकालत की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' का विरोध करने वालों की दलील है कि 'इसे अपनाना संविधान की

मूल संरचना का उल्लंघन होगा। ये अलोकतांत्रिक, संघीय ढांचे के विपरीत, क्षेत्रीय दलों को अलग-अलग करने वाला और राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा। चुनाव दो चरणों में कराए जाएं। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाएं। दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव हों।

क्या संविधान के खिलाफ है एक देश-एक चुनाव ?

सरकार एक देश-एक चुनाव की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। इसको

लेकर बनी कोविन्द की रिपोर्ट स्वीकार की जा चुकी है। अब देखना है कि आने वाले समय में इस मुद्दे के रास्ते में कौन-कौन सी अड़चन आने वाली है। हालांकि आगे का रास्ता कठिन है। वन नेशन, वन इलेक्शन कैसे संभव हो सकता है और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार देने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए 543 में से 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास हैं 293 सदस्य। राज्यसभा में अभी 234 सदस्य हैं, जिनमें से एनडीए के 126 हैं। दो-तिहाई से 30 कम। अगर राज्यसभा के सभी 250 सदस्य मतदान के वक़्त मौजूद हों तो दो-तिहाई समर्थन के लिए 164 वोट चाहिए होंगे। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के सौ दिन के भीतर नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव करवाने की सिफ़ारिश की गई है। इसके लिए जो संविधान संशोधन विधेयक पारित करना होगा, उसमें कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से भी मंजूरी लेने की जरूरत होगी। अभी 28 में से 19 राज्यों में एनडीए की सरकार है। तो, इस लिहाज से राज्यों में मुश्किल नहीं भी आ





सकती है, लेकिन वहां तक जाने से पहले लोकसभा और राज्यसभा पार करना मुश्किल दिख रहा है। एक साथ चुनाव करने की यह व्यवस्था 2029 से लागू होगी या 2034 से। यह कहना अभी मुश्किल है।

एक देश-एक चुनाव से फायदा क्या?

एक देश-एक चुनाव के समर्थन में कई तर्क दिए जाते रहे हैं। इनमें पहला तो यही है कि यह कोई नई बात नहीं है, 1967 तक ऐसा ही होता था। अब अलग-अलग चुनाव होने के चलते पार्टियों को ज़्यादातर वक़्त चुनावी मोड में ही रहना पड़ता है। इससे सरकार का कामकाज और विकास प्रभावित होता है। एक और तर्क खर्च का है। वन नेशन, वन इलेक्शन के समर्थक कहते हैं कि आजकल चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं और इस कदम से पैसे की बचत होगी। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000

भारत में कई छोटी पार्टियां हैं, जो कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में एक देश-एक चुनाव में छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा है, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों को इससे फायदा होगा।

करोड़ रुपये खर्च हुए थे। समर्थक ये भी कहते हैं कि 1999 और 2018 में विधि आयोग भी एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दे चुका है।

विरोधी बताते हैं संविधान की भावना के खिलाफ

एक देश-एक चुनाव का विरोध करने वालों के भी अपने तर्क हैं। उनकी चिंता है कि इसे संभव बनाने के लिए कई

विधानसभाओं को उनके तय कार्यकाल से पहले भंग करना होगा, जो जनता की इच्छा और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होगा। इनका कहना है कि सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि इसे संभव बनाने के लिए संसद का दो-तिहाई समर्थन लेने के अलावा आधे राज्य विधानसभाओं की भी सहमति लेनी होगी। दूसरा तर्क है कि यह व्यवस्था सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान का महत्व कम कर देगी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर मध्यावधि चुनाव कि स्थिति बनेगी। ईवीएम की उपलब्धता और सुरक्षा इंतजाम आदि से जुड़ी चिंताएं भी हैं।

छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा

भारत में कई छोटी पार्टियां हैं, जो कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में एक देश-एक चुनाव में छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा है, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों को इससे फायदा होगा।

2029 में एक-देश, एक-चुनाव संयुक्त चुनाव कराने की तैयारी



प्रमोद भार्गव

2029 में एक देश, एक चुनाव, यानी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ निकाय व पंचायत चुनाव भी एक साथ कराने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि 2029 के पहले एक साथ चुनाव का प्रबंध कर दिया जाएगा। साफ है, सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी वादे को क्रियान्वित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। साफ है,

केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि सरकार अपने अजेंडे पर आगे बढ़ती रहेगी। उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव कराने के नजरिए से शीतकालीन सत्र में इस विधेयक और इस प्रक्रिया को पूरी करने वाले संशोधन विधेयकों को पारित कराने की शुरुआत संसद में हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस समेत करीब 15 राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि भाजपा समेत 32 राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं।

एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इस समय जिन राज्य सरकारों का कार्यकाल बचा होगा, वह लोकसभा चुनाव तक ही पूरा मान लिया जाएगा। वैसे भी आजादी के बाद

1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे हैं, लेकिन 1968 और 1969 में समय के पहले ही कुछ राज्य सरकारें भंग कर दिए जाने से यह परंपरा टूट गई। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में करीब 18 संशोधन करने होंगे। इनमें से कुछ बदलावों के लिए राज्यों की भी अनुमति जरूरी होगी। यदि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव भी साथ साथ होते हैं तो फिर मतदाता सूची तैयार निर्वाचन आयोग कराएगा। इस हेतु अनुच्छेद 325 में परिवर्तन करना होगा। साथ ही अनुच्छेद 324 ए में संशोधन करते हुए निगमों और पंचायतों के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के

साथ करा लिए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 368 ए के तहत इस संशोधन विधेयक को आधे राज्यो से भी पास करना जरूरी होगा। इसी अनुरूप केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अलग से संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी।

इस रिपोर्ट से पहले संसदीय समिति भी देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालात कर चुकी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि लोकसभा, विधानसभा,

अलग-अलग चुनाव होने पर हारने वाले कई प्रत्याशी एक बार फिर किस्मत आजमाने के मूड में आ जाते हैं, वहीं विधायकों को भी लोकसभा और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो सीट खाली होती है, उसे फिर से छह माह के भीतर भरने की संवैधानिक बाध्यता के चलते चुनाव कराना पड़ता है। नतीजतन जनता के साथ-साथ प्रत्याषी को भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी

के लिए कम से कम 18 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाना जरूरी होगा। विधि आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और संविधान समीक्षा आयोग तक इस मुद्दे के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। यदि विपक्षी दल सहमत हो जाते हैं तो दो तिहाई बहुमत से होने वाले ये संशोधन कठिन कार्य नहीं हैं। 2024 में मोदी सरकार की बहाली हो गई है, इससे एक साथ चुनाव की उम्मीद बढ़ गई



नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ होते हैं तो लंबी चुनाव प्रक्रिया के चलते मतदाता में जो उदासीनता छ जाती है, वह दूर होगी। एक साथ चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता को एक ही बार घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचना होगा, अतएव मतदान का प्रतिषत बढ़ जाएगा। यदि यह स्थिति बनती है तो चुनाव में सरकारी धन कम खर्च होगा। 2019 के आम चुनाव में करीब 60,000 करोड़ खर्च हुए थे और 2024 के चुनाव में लगभग एक लाख करोड़ स्पष्ट खर्च हुए हैं। एक साथ चुनाव में राजनीतिक दल और प्रत्याषी को भी कम धन खर्च करना होगा। दरअसल

उदासीनता झेलनी पड़ती है। इस कारण सरकारी मशीनरी की जहां कार्य संस्कृति प्रभावित होती है, वहीं मानव संसाधन का भी ह्यास होता है।

चूंकि संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग इकाइयां हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संविधान में समानांतर किंतु भिन्न-भिन्न अनुच्छेद हैं। इनमें स्पष्ट उल्लेख है कि इनके चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर होने चाहिए। लोकसभा या विधानसभा जिस दिन से गठित होती है, उसी दिन से पांच साल के कार्यकाल की गिनती शुरू हो जाती है। इस लिहाज से संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव

है। इस दौरान ईवीएम समेत अन्य चुनावी उपकरणों की जरूरत पूरी कर ली जाएगी।

अनेक असमानताओं, विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से बंधा है। निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्र को एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था देती है, जिससे भिन्न स्वभाव वाली राजनीतिक शक्तियों को केंद्रीय व प्रांतीय सत्ताओं में भागीदारी का अवसर मिलता है। नतीजतन लोकतांत्रिक प्रक्रिया गतिशील रहती है, जो देश की अखंडता व संप्रभुता के प्रति जवाबदेह है। देश में मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी है। गोया, यदि बार-बार चुनाव की स्थितियां

बनती हैं तो मनुष्य का ध्यान बंटता है और समय व पूंजी का क्षरण होता है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रशासनिक शिथिलता दो-ढाई महीने तक बनी रहती है, फलतः विकास कार्य और जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं। एक साथ चुनाव के चलते सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनाव ड्यूटी का मानसिक तनाव नहीं झेलना पड़ेगा।

एक साथ चुनाव के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि देश प्रत्येक छह माह बाद चुनावी मूड में आ जाता है, लिहाजा सरकारों को नीतिगत फैसले लेने में तो अड़चनें आती ही हैं, दूसरे नीतियों को कानूनी रूप देने में अतिरिक्त विलंब भी होता है। यह तर्क अपनी जगह जायज है। वैसे भी राजनीतिक दलों की महत्ता तभी है जब वे नीतिगत फैसलों को अधिकतम लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपने सुझाव दें व उन्हें विधेयक के प्रारूप का हिस्सा बनाने के लिए नैतिक दबाव बनाएं। ऐसा नहीं है कि एक साथ चुनाव का विचार कोई नया विचार है। 1952 से लेकर 1967 तक चार बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ ही हुए हैं। इंदिरा गांधी का केंद्रीय सत्ता पर वर्चस्व कायम होने के बाद राजनीतिक विद्वेष व बेजा हस्तक्षेप के चलते इस व्यवस्था में बदलाव आना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी को विपक्ष की जो सरकार पसंद नहीं आती थी, उसे वे कोई न कोई बहाना ढूंढकर अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति से बर्खास्त करा देती थीं। नतीजतन मध्यावधि चुनावों की परिपाटी पड़ती चली गई। इससे राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव कराने की बाध्यता निर्मित हो गई। अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त होने के बाद पीवी नरसिंह राव ने भी भाजपा शासित कई राज्य सरकारों को गिरा दिया था। वस्तुतः ऐसा अवसर आ गया कि देश में कहीं न कहीं चुनाव की डुगडुगी बजती रहती है। देश का



लगभग 97 करोड़ मतदाता किसी न किसी चुनाव की उलझन में जकड़ा रहता है।

चूंकि संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का उल्लेख तो है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ कराने का हवाला नहीं है। संविधान में इन चुनावों का निश्चित जीवनकाल भी नहीं है। वैसे यह कार्यकाल पांच वर्ष के लिए होता है, लेकिन बीच में सरकार के अल्पमत में आ जाने के कारण या किसी अन्य कारण के चलते सरकार गिर या गिराई जा सकती है। केंद्रीय विधि आयोग ने 2018 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि पांच साल के भीतर यदि सरकार के भंग होने की स्थिति बने तो रचनात्मक अविश्वास मत हासिल किया जाए। मसलन, किसी सरकार को लोकसभा या विधानसभा के सदस्य अविश्वास मत से गिरा सकते हैं, तो इसके विकल्प में जिस दल या गठबंधन पर विश्वास हो या जिसे विश्वास मत हासिल हो जाए, उसे बतौर नई सरकार की शपथ दिला दी जाए। कुछ विपक्षी दल एक साथ चुनाव के पक्ष में शायद इसलिए नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा होने पर जिस दल

**ONE NATION
ONE ELECTION**

ने अपने पक्ष में माहौल बना लिया तो केंद्र व ज्यादातर राज्य सरकारें उसी दल की होंगी ? जैसे कि सत्रहवीं (2019) लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रवाद की हवा के चलते भाजपा नेतृत्व वाले राजग को बड़ा जनादेश मिला था। ऐसे में यदि विधानसभाओं के भी चुनाव हुए होते तो कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दलों का भी सूपड़ा साफ हो गया होता ? हालांकि ऐसा हुआ नहीं था।

बार-बार चुनाव की स्थितियां निर्मित होने के कारण सत्ताधारी राजनीतिक दल को यह भय बना रहता है कि उसका कोई नीतिगत फैसला ऐसा न हो जाए कि दल के समर्थक मतदाता नाराज हो जाएं। लिहाजा सरकारों को लोक-लुभावन फैसले लेने पड़ते हैं। वर्तमान में अमेरिका सहित अनेक ऐसे देश हैं, जहां एक साथ चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। गोया, भारत में भी यदि एक साथ चुनाव की प्रक्रिया 2029 से होती है तो केंद्र व राज्य सरकारें बिना किसी दबाव के देश व लोकहित में फैसले ले सकेंगी। सरकारों को पूरे पांच साल विकास व सुशासन को सुचारू रूप से लागू करने का अवसर मिलेगा।

छत्तीसगढ़वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत



छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार को लगभग आठ माह हो गये हैं। इन आठ माह में प्रदेश की सरकार ने जनकल्याण के कई कार्य किये हैं या प्रारंभ कर दिये हैं। सभी जनकल्याणकारी योजनाओं पर एक साथ काम कर रही है। स्कूल, स्वास्थ्य, नक्सलवाद, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लेकिन साय सरकार प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। भूपेश शासन में प्रदेश को जो पीछे पहुंच चुका है उसे आगे लाने में बहुत कुछ करना होगा। हम मानते हैं कि सरकार जिस तेजी के साथ कामों को आगे बढ़ा रही है, निश्चित ही यह एक सही दिशा है। इस दिशा में सरकार को उन पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा जो पिछले कई वर्षों से अनछुए रहे हैं। रोजगार, कौशल विकास, नक्सलवाद, नारी शक्ति, किसान कल्याण, आदिवासी उत्थान जैसे अनेक मामले हैं जिन पर सरकार को युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। सरकार को चरणबद्ध ढंग से महिलाओं, बच्चों, बेटियों, युवाओं, बुजुर्गों और कामगारों के लिये लाभकारी योजनाओं का निर्माण कर उन्हें संबल देने का कार्य करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था पर भी काफ़ी ध्यान देना होगा। क्योंकि देखने में आ रहा है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जिसका लाभ विपक्ष लेना चाहता है। मुख्यमंत्री साय को इस विशेष विभाग पर भी खासी नजर रखनी होगी। कवर्धा की घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया है।

विजया पाठक

अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जो जमीनी स्तर पर लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। ऐसी ही एक पहल है नियत नेलनार योजना, जो माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल और स्कूल जैसे आवश्यक संसाधनों के विकास पर केंद्रित है। दूरदराज के आदिवासी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास भी जारी हैं। भारत के सबसे कम साक्षर जिलों में से एक बीजापुर में माओवादियों द्वारा बंद किए गए 28 स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। इसके अलावा, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय बोलियों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 18 स्थानीय भाषाओं और बोलियों में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। पीएससी परीक्षा घोटाले को लेकर युवाओं के गुस्से और हताशा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की

अनुशंसा की। शासकीय भर्ती आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने से युवाओं के मन में खुशियां देखने को मिली है।

महिला सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अधिकांश वायदों को पूरा करने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तब

उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलम्बन और सशक्तिकरण के लिए ठोस व दूरगामी रणनीति बनानी पड़ती है। प्रदेश के 70 लाख विवाहित महिलाओं के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण महतारी वन्दन योजना से मिली है। प्रदेश के चारों तरफ विवाहित महिलाओं को हर माह एक हजार रूपए दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा विवाहित माताओं-बहनों के खाते में राशि देने के पीछे





आर्थिक सशक्तीकरण करना, उनके आर्थिक हालात को बेहतर करना प्रमुख उद्देश्य है। यहां यह भी जरूरी है कि सिर्फ राशि देकर नारी शक्ति का उत्थान नहीं हो सकता है। महिलाओं को स्वरोजगार जैसे कदम भी उठाना होंगे। जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और स्वावलंबी बन सकें।

किसान कल्याण

हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। प्रदेश की सरकार को चाहिए कि

वह विशेष वर्ग के कल्याण के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके। हालांकि साय सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ रुपये के समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किसानों के खाते में किया गया, वहीं 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़



रुपे अन्तरित की गई। खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इसके अलावा किसानों को दो साल के धान के बकाया बोनस राशि 03 हजार 716 करोड़ रुपये देने जैसे साहसिक निर्णय लिए हैं। सरकार बनते ही तेन्दूपत्ता प्रति मानक बोरा 5 हजार 500 रुपये की गई, जिससे 12 लाख 50 हजार से अधिक तेन्दूपत्ता संग्रहकों को लाभ मिल रहा है। सरकार की यह पहलें लाभदायक हो सकती हैं लेकिन इसके अलावा भी कई मामले हैं जिन पर काम करके किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है।

नक्सलवाद

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है। प्रदेश के कापड़े जिले इस समस्या से जूझ रहे हैं। जिस बस्तर अंचल की पहचान सुंदर प्राकृतिक परिवेश और अकूत संसाधनों से है तथा यहां के भोलेभाले आदिवासियों की कला संस्कृति ने देश और दुनिया को अपनी ओर खींचा है। इस स्वर्ग को दूषित करने का काम कुछ नक्सलवादी कर रहे हैं। पिछली भूपेश सरकार ने इस समस्या पर कुछ काम नहीं किया। जिसके ही परिणाम रहे कि यह समस्या जस की तस रही। लेकिन प्रदेश में साय सरकार के अडिग निर्णय, बेहतर रणनीति का ही परिणाम है कि महज छह माह में 129 माओवादियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किया है, 488 गिरफ्तार हुए हैं 431 आत्म समर्पण किया और इस तरह बस्तर की उम्मीद की नई रौशनी देखने को मिलने लगी है। सुरक्षा और विकास के दोहरे मोर्चे पर काम करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज अनुपात के हिसाब से छत्तीसगढ़ का बस्तर देश में सबसे सैन्य संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है, बस्तर डिवीजन में प्रत्येक 09 नागरिकों के पीछे एक पैरामिलिट्री का जवान है। जल्द ही इन क्षेत्रों में सुरक्षाबलों के 250 से ज्यादा कैम्प



और नियद नेल्लानार से 58 नए कैम्प स्थापित होंगे ताकि सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का दायरा बढ़ सके। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा बंद 28 स्कूल अब खुल गए हैं। इतना भर करने से नक्सलवाद की समस्या स्थायी रूप से हल नहीं होने वाली है। इसके लिए सरकार को कुछ ऐसे दूरगामी कदम उठाने होंगे जो जिससे जो लोग मुख्य धारा से भटक गये हैं वह वापिस मुख्य धारा में आ जाये।

आदिवासी समाज के लिए तत्पर है सरकार

छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है। प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग इस समाज का है। जिसके कल्याण और बेहतरी के लिए सरकार को हमेशा तत्पर रहना होगा। आदिवासियों की आजीविका और संस्कृति को सहेजना और संवारना होगा। हालांकि प्रदेश में नई सरकार आने के बाद सरकार आदिवासी युवाओं के सुनहरे भविष्य की

नींव भी मजबूत कर रही है, इसी क्रम में नई दिल्ली के ट्रायबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर अब 185 कर दी गई है। इस निर्णय से देश राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की तैयारी करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अब इस हॉस्टल में तीन गुने से भी अधिक सीटें उपलब्ध होंगी। इसी तरह आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण भी किया जाएगा।

गरीब कल्याण

प्रदेश के 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पांच वर्षों तक मुफ्त अनाज देने जैसे निर्णय साबित कर रहे हैं कि सरकार गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। खुद का घर, पक्का मकान यह सब सुनने में एक गरीब परिवार के लिए दिन में देखने वाले स्वप्न की तरह होता है। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण की दिशा में प्रदेश जोरशोर से आगे बढ़ चुका है।



राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा और उससे उपजे सवाल



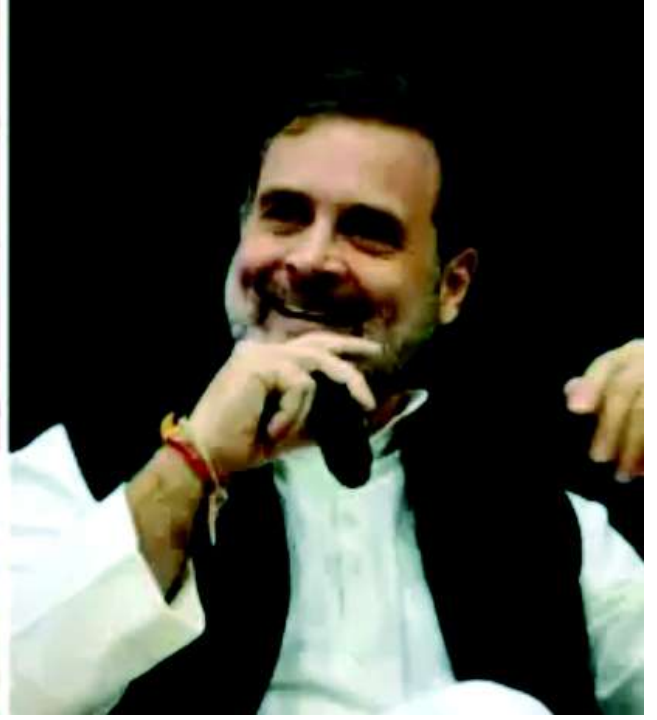
रघु ठाकुर

राहुल गांधी का वास्ता निरंतर विवादों से रहता है। कुछ इसलिये कि एक राजनैतिक समूह उन्हें निरंतर विवादास्पद बनाये रखना चाहता है। इसलिये वे अपने स्वभाव के चलते बहुत दूर तक विवाद पैदा करने से नहीं बच पाते। कई बार ऐसा लगता है कि वे बहुत शीघ्रता में हैं। एक दृष्टिकोण से यह शीघ्रता स्वाभाविक भी है क्योंकि अगले चुनाव तक वे शायद 60 की उम्र तक पहुँच जाएंगे। और अगर वह चूकते हैं तो फिर राजतिलक दूर की कौड़ी बन जायेगा। हालाँकि हमारे देश में सत्ता की

कोई उम्र नहीं होती, अब तो इस मामले में भारत विश्व गुरु जैसा बन गया है। जिन देशों में पहले राष्ट्राध्यक्षों या प्रधानमंत्री की उम्र सीमा 40-50 के अंदर होती थी यथरू अमेरिका, रूस आदि अब इन देशों में भी उम्र सीमा 70 के पार पहुँच चुकी है।

अभी राहुल जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अमेरिका के दौरे पर गये और वहाँ उन्होंने जो कहा था जो मुलाकातों की हैं, उनको लेकर देश में काफी चर्चा भी चली और प्रतिक्रियाएँ भी हुईं। एक तो उनकी मुलाकात अमेरिका सीनेट की एक महिला मेंबर से हुई। वे लगातार भारत के खिलाफ

बोलती रहीं और वह जम्मू-कश्मीर की अलगाववादी समर्थक भी हैं। यह सुविदित तथ्य है कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन अमेरिकी तंत्र से समर्थन पाते रहे हैं और उन्हें अमेरिका में रहकर अपने एजेंडा को बढ़ाने के लिये सभी अवसर और सुविधाएँ मिलती हैं। लगभग एक दशक पूर्व तो भारत और दुनिया के कई देशों के पत्रकारों को लगभग प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर को अलग करने वाले संगठन निमंत्रण देकर बुलाते थे, उनके खर्च उठाते थे, उन्हें भेंट देते थे, और उन्हें वापिस जाकर क्या प्रचारित करना है इसके आंकड़े भी देते थे। ऐसा कहा



जाता है कि यह अलगाववादी संगठनों के पीछे सीआईए की भूमिका होती है। अमेरिकी राजनयिक का यह तरीका रहा है कि वे समस्याओं को पैदा कराते हैं फिर उनके नाम पर व्यापारिक राजनैतिक सौदे कराते हैं और अगर सौदा न पटे तो फिर संबंधित देश में अस्थिरता पैदा करने में उन संगठनों का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल श्री राहुल गांधी ने भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जो दौरा किया, इसमें उन्होंने जो बातें कहीं हैं, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं-

(यें बिन्दु भी भारतीय मीडिया में अलग-अलग आये हैं और उनके संपूर्ण भाषण का कोई विवरण एक मुश्त मुझे पढ़ने को नहीं मिला।)-

1. दैनिक जनसत्ता के 11 सितंबर के अनुसार उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया गया।

2. उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा

कि आरक्षण खत्म करने के बारे में कांग्रेस तब सोचेगी जब देश में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी। देश के वित्तीय आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि आदिवासियों को 100 रुपये में से 10 पैसे, दलितों को 100 रुपये में से 5 पैसे और अन्य पिछड़ा

आरएसएस धर्म, भाषाओं और समुदायों को अन्य की तुलना में कमतर मानता है और इसी बीच में उन्होंने दर्शकों में पहली पंक्ति में बैठे एक सिख व्यक्ति से संवाद करते हुए कहा लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है। वह गुस्से से जा सकता है। ऐसी ही लड़ाई सभी धर्मों के लिए है।

वर्ग को 100 रुपये में से लगभग इतने ही पैसे मिलते हैं। सच्चाई यह है कि उन्हें उचित भागीदारी नहीं मिल रही है।

3. उन्होंने कहा कि आरएसएस धर्म, भाषाओं और समुदायों को अन्य की तुलना में कमतर मानता है और इसी बीच में उन्होंने दर्शकों में पहली पंक्ति में बैठे एक सिख व्यक्ति से संवाद करते हुए कहा लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है। वह गुस्से से जा सकता है। ऐसी ही लड़ाई सभी धर्मों के लिए है।

4. उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस वस्तुतः यही कहता है कि कुछ राज्य दूसरे राज्य से कमतर हैं। कुछ धर्म, समुदाय और भाषायें एक दूसरे धर्म, समुदाय से कमतर हैं।

जहाँ तक उनका पहला कथन का संबंध है निसंदेह देश में मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों पर राज्य की दखल बढ़ी है। जांच एजेंसियों का दलीय पक्षपात



के आधार पर भाजपा सरकार ने दुस्प्रयोग किया है। उससे देश में एक भय व्याप्त हुआ है। जाँच एजेंसियों के दुस्प्रयोग पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टिप्पणी की गई है कि सीबीआई को तोता बनकर पिंजरे में रहने की जगह बाहर निकलना चाहिये। गुप्तचर संस्थाओं का दुस्प्रयोग हो रहा है हालांकि 10 वर्ष के पूर्व की सरकारों द्वारा भी दुस्प्रयोग होता रहा है, यह भी सही है, परंतु मूल प्रश्न है कि क्या अपने देश के आंतरिक हालात की चर्चा विदेशों में जाकर, उनके मंचों पर जाकर, होना चाहिये, यह परंपरा हमारे देश में नहीं रही है। डॉ. राममनोहर लोहिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के आलोचक थे परंतु उन्होंने अपनी अमेरिकी यात्रा में उनकी चर्चा नहीं की, बल्कि जब वहाँ की प्रेस ने उनसे इस बारे में टिप्पणी मांगी तो उन्होंने कहा कि यह हमारे

देश का आंतरिक मसला है। इसके लिये मैं अमेरिका नहीं आया हूँ। स्व. अटलबिहारी वाजपेयी ने अमेरिका यात्रा में भारत सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। डॉ. लोहिया तो इससे एक कदम आगे जाकर अमेरिका में अमेरिका की व्यवस्था को ललकारा और उनके रंगभेद नीति के विरुद्ध न केवल सार्वजनिक रूप से कहा था बल्कि उनके नियमों को तोड़कर आंदोलन किया व गिरफ्तारी दी थी। जिस अमेरिका में जाकर राहुल जी भारतीय लोकतंत्र के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं उस अमेरिका में स्वतः लोकतंत्र की स्थिति क्या है। आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के वर्तमान प्रत्याशी ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति जो वाइडेन के बीच जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है वह कुछ अर्थों में भारत से भी बदतर है। पिछले दशक में अमेरिकी

लोकतंत्र जिसे लोग एक जमाने में एक आदर्श लोकतंत्र मानते थे यद्यपि इस पूंजीवादी लोकतंत्र का आज सारी दुनिया में हास्य का विषय बना हुआ है परंतु राहुल जी ने अमेरिकी लोकतंत्र की खामियों की चर्चा करने की बजाय अपने देश के लोकतंत्र की खामियों को बताने के लिए जो मंच चुना वह उचित नहीं कहा जा सकता है।

आरक्षण के बारे में राहुल जी की राय इस अर्थ में सच्चाई के करीब है कि आरक्षण को चतुराई या चालाकी के साथ खत्म करने का या अप्रभावी करने के तरीके सरकारें चुन रही हैं। हालांकि उनसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपकी पार्टी ने मंडल कमीशन के रपट का 1990 में समर्थन क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी ने ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का समर्थन किस आधार पर किया। वर्ष 2011 में हुई जनगणना की जाति संख्या की रपट

प्रकाशित क्यों नहीं कराई? वर्तमान भाजपा सरकार और उसकी मातृ संस्था आरक्षण के पक्ष में नहीं है। बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व जब देश में जातीय जनगणना की बात उठी तो संघ के इशारे पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने यह कहकर तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया कि हमारा विश्वास तो युवा, गरीब, किसान, मजदूर नामक जातियों में है। याने जो भाषा 1950 के दशक में साम्यवादी मित्र बोलते थे वह भाषा जातिवाद पर पर्दा डालने के लिए प्रधानमंत्री व भाजपा ने बोलना शुरू किया। परंतु अब जब भाजपा 400 पार के नारे से घटकर 240 पर सिमट गई तब संघ में भी हलचल हुई व भविष्य के खतरे सामने आने लगे। हाल ही में संघ ने केरल में अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया कि जातीय जनगणना हो सकती है बर्शते वह राष्ट्रीय हित में की जाये। यह शब्दावली केवल अपने अपराध को छुपाने वाली शब्दावली है और संघ के इस अघोषित अनुमति के बाद यह संभावना बढ़ी है कि अब सरकार जातीय जनगणना करायेगी। परंतु इन सवालों की चर्चा भी उस अमेरिका में अर्थहीन है जहां आज भी रंगभेद प्रभावी है और गोरे अधिकारी सरेआम काले की गर्दन पर पैर रखकर जान ले लेते हैं। क्या किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका के बाहर किसी दूसरे देश में अपने देश के रंगभेद की चर्चा की है।

तीसरा बिन्दु तो और भी अनुचित है, जिसमें कि राहुल गांधी ने कहा कि विषय यह है कि क्या कोई सिख अपना धर्म मान सकता है, कड़ा और पगड़ी पहन सकता है आदि। यह तो कोई सामान्य व्यक्ति, क्या भारतीय, क्या विदेशी और कोई सिख भाई कह देगा कि भारत में सिख भाईयों को, जैन-बुद्ध और मुस्लिम भाईयों को, अपनी धार्मिक परिपाटियों को मानने पर कोई रोक नहीं है। यह इसलिये भी उनका आश्चर्यजनक कथन लगा, क्योंकि सिख ही



क्या बल्कि सभी धर्मों के मामले में कांग्रेस पार्टी का अतीत साफ सुथरा नहीं है। कांग्रेस सरकार के जमाने में ही राममंदिर में मूर्तियां रखी गई थीं, फिर ताला खोला गया था और उसका जो अंत होना था वह सबके सामने हैं। कांग्रेस के जमाने में ही मेरठ, भागलपुर में भयानक दंगे हुए थे जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई मारे गये थे और बर्बाद हो गये थे। कांग्रेस सरकार के जमाने में ही तत्कालीन मप्र और वर्तमान छग में जैन मुनि आचार्य तुलसी के पंथवालों ने दंगे किये थे और 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किस प्रकार सिख समाज के ऊपर हमले, हत्याएं और लूटपाट हुई थी, उसे कौन भुला सकता है। सिखों की नृशंस हत्या के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी से इन हत्याओं को लेकर प्रश्न पूछा गया था तो वह बोले कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिल जाती है और उसके बाद के घटनाक्रम सभी को पता है। नेता प्रतिपक्ष के जिम्मेदार पद पर और कांग्रेस पार्टी के शासक परिवार के अंग रहते हुए कम से कम राहुल जी को इन जखमों को कुरेदने की आवश्यकता नहीं थी। उनके इन कथन के परिणाम कितने दूरगामी और भयानक हो सकते हैं, शायद यह कल्पना उन्होंने नहीं की।

हालांकि भाजपा के प्रवक्ताओं ने उनके बयान के बाद उन्हें राष्ट्रद्रोही कहना शुरू कर

दिया। मैं उन्हें राष्ट्रद्रोही तो नहीं मानता हूँ परंतु उनके इस बयान को गैर जिम्मेदाराना, गैर जरूरी और देश की छवि के साथ-साथ उनके दल की छवि भी बिगाड़ने वाला मानता हूँ। शिवसेना (एकनाथ) के एक विधायक ने तो यह सार्वजनिक बयान दिया है कि जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा, उसे वे 11 लाख रुपये देंगे। यह बयान, अलोकतांत्रिक, अनुचित व आपराधिक है। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री शिंदे स्वतः अपने पक्ष के विधायक के विरुद्ध कार्यवाही करते तो इससे उनकी लोकतांत्रिक छवि भी मजबूत होती। परंतु उनसे अपेक्षा अर्थहीन है। श्री रवनीत सिंह बिट्टू रेल राज्यमंत्री भारत सरकार के हैं तथा पुराने कांग्रेस के रहे हैं ने कहा कि श्री राहुल गांधी हिन्दुस्तानी नहीं है। श्री बिट्टू कांग्रेस से भाजपा में गये हैं तथा संभव है कि भाजपा में अपने नंबर बढ़वाने के लिये वे ऐसे बयान दे रहे हों, जो ऊपर वालों को खुश कर सकें। परंतु एक केन्द्रीय मंत्री के नाते उनका बयान बिलकुल भी उचित नहीं है। और अगर वे ईमानदारी से यह मानते हैं तो उन्हें अपने गृहमंत्री से कहना चाहिये कि वे श्री राहुल गांधी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करायें। देश नेता प्रतिपक्ष से एक ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है। राहुल जी अभी अर्धे उम्र में हैं परंतु सुधार के लिये कोई भी उमर ज्यादा नहीं होती।

क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका डेलावेयर में भारत का आगाज़



किशन भावनानी

वैश्विक स्तर पर अमेरिका की मेजबानी में डेलावेयर अर्कमेरे अकादमी अमेरिका में संपन्न हुए चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनियां की नज़रें लगी हुई थी, जो काफी सफल रहा। शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन, उभरती टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आतंकवाद विरोधी देशों में सहयोग पर चर्चा निर्धारित थी, जिसका सकारात्मक सफल परिणाम देखने को मिला। इसके पूर्व 21 सितंबर 2024 को देर रात क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम बाइडन के आवास ग्रीनविले पहुंचे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। बाइडन ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम को भी डेलावेयर स्थित अपने घर पर

आमंत्रित किया। यह मुलाकात अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से कुछ समय पहले हो रही है, इसलिए इस दौर का खास माना जा रहा है। शिखर सम्मेलन की बैठक में आए भारत अमेरिका सहित ऑस्ट्रेलिया जापान में भी द्विपक्षीय चर्चाएं की। इस सम्मेलन से विस्तारवादी देश को बेचैनी होना लाजिमी

शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन, उभरती टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आतंकवाद विरोधी देशों में सहयोग पर चर्चा निर्धारित थी, जिसका सकारात्मक सफल परिणाम देखने को मिला।

भी है क्योंकि (1) यह मंच भारत को वैश्विक सप्लाइ चैन से जोड़कर सेमीकंडक्टर, 5जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबो रिएक्टर जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहा है (2) चार विकसित देश के यारों की बैठक पर विश्व की नज़रें थी, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया इंडो पॅसिफिक क्षेत्र पर इसकी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी व भारत के कद प्रतिष्ठा व महत्व में बढ़ोतरी होगी। चूंकि क्वाड शिखर सम्मेलन डेलावेयर में भारत का आगाज़ हुआ, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, क्वाड शिखर सम्मेलन में बैठे चार यारों को दुनियां नें देखे, भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान की जबरदस्त बॉन्डिंग सफल द्विपक्षीय बैठक इंडो पॅसिफिक सुरक्षा व अहम समझौता से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी।

बात अगर हम क्वाड शिखर सम्मेलन के सफल परिणामों व भारतीय पीएम के संबोधन की करें तो,क्वाड शिखर सम्मेलन में भारतीय पीएम ने कहा, हमारी बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय

और पूरक बनने के लिए है। हमें 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में खुशी होगी। पीएम ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वैश्विक मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहते हैं। खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की वकालत करते हैं। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में करने में हमें बहुत खुशी होगी। पीएम ने कहा कि क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए वेलमिंगटन से बेहतर जगह नहीं हो सकती। बात अगर हम क्वाड शिखर सम्मेलन में

को बनाने के पीछे की मकसद की करें तो इसका निर्माण इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व को बनाए रखने के लिए किया गया था। इसका मकसद नियम आधारित व्यवस्था बनाना, नेविगेशन की स्वाधीनता और इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करना भी है। वैसे तो क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है फिर भी यह मालाबार जैसे सैन्य अभ्यास की सहूलियत देता है। असल में क्वाड को इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने का एक तरीका भी माना



अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। मुक्त, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने साथ मिलकर स्वास्थ्य, सुरक्षा, महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी पहल की हैं। हमारा संदेश स्पष्ट है- क्वाड यहाँ रहने, सहायता करने, साझेदारी करने

सदस्यों रूपी चार यारों के मिलने से चीन को बेचैनी की करें तो, बाइडन की कोठी में बैठे पीएम समेत क्वाड के 4 यार, चीन के लिए चक्रव्यूह! क्वाड 'शुरू से चीन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होता आया है। बता दें कि इस समूह की स्थापना का मूल मंत्र समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना रहा है। क्वाड से भारत को भी फायदा है, इस ग्रुप में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताक और बढ़ी है। अगर बात क्वाड

जाता है। जानकार मानते हैं कि क्वाड की वजह से चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता में कमी आई है। क्वाड के देश भारत के वैश्विक व्यापार के लिए क्वाड के जरिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। क्वाड के सप्लाय चैन से जुड़कर भारत अपनी उत्पादन क्षमता को और मजबूत कर रहा है। इस बीच चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर काफी दबाव बनाया, इसका नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने



इस संगठन से दूरियां बना ली थीं। चीन ने बीते कुछ सालों में साउथ-ईस्ट एशिया में बेहद आक्रामक तरीके से अपना विस्तार किया है। इसका कुछ हद तक साउथ-ईस्ट एशिया के अलग अलग देशों पर भी पड़ा है। भारत को भी इसकी जानकारी है। भारत भी बीते लंबे समय से चीन के प्रभाव को कम करने की दिशा में लगातार सकारात्मक बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में क्वाड भारत को वैकल्पित कनेक्टिविटी वाली परियोजनाओं और क्षेत्रीय विकास के प्रयास करने के लिए और प्रेरित करता है। क्वाड के जरिए ही भारत की पहुंच महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और कच्चे माल तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। यह मंच भारत को वैश्विक सप्लाइ चेन से जोड़कर सेमीकंडक्टर, 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद दे रहा है।

बात अगर हम 25 हजार भारतीयों से मुलाकात की जहां भारतीय-अमेरिकी

समुदाय को संबोधित किया। आयोजकों के अनुसार, प्रवासी कार्यक्रम के लिए 25, हजार से अधिक लोगों ने टिकटों के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। इस कार्यक्रम से भारत और उसके प्रवासी समुदाय के बीच मजबूत संबंधों को मजबूती मिलेगी। बता दें कि प्रवासी समुदाय की अमेरिका-भारत संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद दोपहर में, पीएम अपने होटल में टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए अमेरिकी व्यापार जगत के नेताओं से भी मुलाकात किए। बैठक के बाद, पीएम वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा, जो रात 10 बजे तक जारी रही।

बात अगर हम 23 सितंबर 2024 को वैश्विक संयुक्तराष्ट्र शिखर सम्मेलन में भाग लेने की करें तो, 23 सितंबर को पीएम भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन' में हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में भविष्य

की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल गवर्नेंस शामिल है। अगर उनसे पहले के सभी वक्ता अपने समय पर आते हैं, तो उनकी बारी दोपहर के आसपास (भारत में रात 9:30 बजे) होगी। वहीं, क्लाइमेट चेंज और सतत आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में पीएम की उपस्थिति वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती नेतृत्व क्षमता को दिखाती है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका डेलावेयर में भारत का आगाज़। क्वाड शिखर सम्मेलन में बैठे चार यार-दुनियां नें देखा सकारात्मक परिणाम रूपी चमत्कार। भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान की जबरदस्त बॉन्डिंग-सफल द्विपक्षीय बैठकें, इंडो पॅसिफिक सुरक्षा व अहम समझौता से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी।



तिरुपति के प्रसाद में पशु चर्बी: गरमाई सियासत आहत हुई हिंदुओं की आस्था

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की टिप्पणी पर उठाए सवाल

समता पाठक

आंध्रप्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के लड्डू में मिलावट को लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच देश के सुप्रीम कोर्ट की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। पिछले दिनों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। करोड़ों सनातन प्रेमियों की आस्था के केंद्र भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट आने के बाद से सियासी धर्म युद्ध छिड़ गया है।

तिरुपति में लड्डू विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नसीहत दी है। राजनेताओं से कहा है कि कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखें, यह लोगों की आस्था का मामला है। अदालत ने कहा कि जब आप एक संवैधानिक पद पर होते हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि देवताओं को राजनीति से दूर रखेंगे। जब इस मामले में जांच चल ही रही थी तो फिर इसे मीडिया में उछालने का क्या मतलब था। दरअसल, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है

कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में बनने वाले लड्डूओं में मिलावटी घी का इस्तेमाल होता था। शीर्ष अदालत ने भी सवाल किया कि इस बात का सबूत कहां है कि यही वह घी है, जिसका इस्तेमाल लड्डू बनाने में हुआ। दरअसल, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि पिछली सरकार के समय तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु चर्बी का उपयोग होता था। उसके बाद इस मामले ने खासा तूल पकड़ लिया। हालांकि इस



आरोप के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर तब तक इसे लेकर विवाद काफी बढ़ गया। इस बात को लेकर भी चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि तिरुपति में घी की आपूर्ति में किस तरह घपला किया गया होगा। इससे पहले जब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जब इस मामले पर अपनी टिप्पणी दी थी तो सारे देश में काफी बवाल मचा और देश के अंदर हिंदु धर्म पर आस्था रखने वाले लाखों लोगों ने इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किये। इसके साथ ही अब राज्य सरकार ने फिलहाल एसआईटी गठित कर दी है जो पूरे मामले पर रिपोर्ट देगी। यहां गौर करने वाली बात यह भी है जब प्रसाद की जांच की जा रही थी तो उससे पहले मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से बयान देने की क्या जरूरत थी।

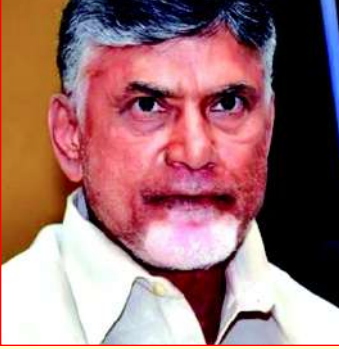
दरअसल, आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार पर मंदिर के प्रसाद में घी की जगह मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाने के आरोपों के बाद से विवाद जारी है। देश भर के संतों में भी नाराजगी देखी जा रही है। संत कह रहे हैं कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की खबर सामने आने के बाद देशभर से विरोध की आवाजें उठने लगी। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि आंध्रप्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। पिछले 300 सालों से मंदिर में आने वाले हिंदू भक्तों को खास 'लड्डू' प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है और इस लड्डू को साल 2014 में जीआई टैग भी मिल चुका

है। इसका मतलब है कि तिरुपति तिरुमला के नाम का यह लड्डू सिर्फ आंध्रप्रदेश के तिरुपति मंदिर में ही मिल सकता है। इस मंदिर को तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर के प्रसाद में इस मिलावट पर लोगों में काफी गुस्सा है।

कुछ ऐसा ही 1984 में भी हुआ था। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कुछ दिनों पहले 1984 में हिंदू धर्म पर आई एक बड़ी विपदा का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि उस वक्त डालडा के नाम से वनस्पति घी बिका करता था। अधिकांश घरों में उसका उपयोग होता था लेकिन उसी साल यानी 1984 में पता चला कि डालडा

हुनका कहना है

मंदिरों की पवित्रता और लोगों की भावनाओं की सर्वोच्च सम्मान करती है हमारी सरकार



कोई ये सोच भी नहीं सकता कि तिरूमला लड्डू को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। पिछले पाँच सालों में वाईएसआर ने तिरूमला की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। इस बात की पुष्टि हो गई है कि तिरूमला लड्डू के घी में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में जांच चल रही है। इसके लिए जो भी दोषी होंगे, उन्हें सज़ा दी जाएगी। हम सबकी जिम्मेदारी है कि वेंकटेश्वर भगवान की पवित्रता की रक्षा करें। हमारी सरकार मंदिरों की पवित्रता और लोगों की भावनाओं की सर्वोच्च सम्मान करती है।

चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, आंध्रप्रदेश

में चर्बी मिली हुई है। इसका सीधा मतलब यह था कि जिस डालडा को हिंदू लोग खाते हैं वो पशुओं के चर्बी से बनी हुई है। यह मामला सामने आने के बाद पूरे देश भर के हिंदुओं में बड़ा रोष था। उस दौरान क्या हुआ था इसी का जिक्र शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया। लोगों को ये भ्रम हो गया कि कहीं ये गाय की चर्बी तो नहीं थी। तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम (टीटीडी) जो प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करता है। उनकी ओर से प्रयोगशाला रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक

पुष्टि नहीं की गई है। आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि पिछली जगनमोहन सरकार में तिरूपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। जुलाई में लिए गए प्रसाद के सैंपल में इसकी पुष्टि भी हुई है। सीएम नायडू ने कहा कि जगनमोहन सरकार ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है ये जुलाई

में लिए गए प्रसाद के सैंपल की है।

कैसे संदेह के घेरे में आया तिरूपति का प्रसाद ?

मंदिर के प्रसाद के लड्डू में चर्बी वाले घी का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। इसके बाद देश भर के मंदिरों में काफी सतर्कता बरती जा रही है। बात सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है। लोग हैरान हैं कि आखिर ये आग लगी कहां से, कैसे पता चला कि लड्डू में चर्बी वाला घी मिलाया जा रहा है। जब भी आप किसी

हुनका कहना है

भगवान के नाम पर राजनीति करना गलत है



सीएम नायडू के आरोप बेबुनियाद हैं। निंदनीय है। भगवान के नाम पर राजनीति करना गलत है। चंद्रबाबू नायडू को राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल करने की आदत है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं। घी में मिलावट के आरोप चंद्रबाबू के 100 दिनों की सरकार के कामों से ध्यान हटाने के लिए लगाए गए हैं।

जगन मोहन रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश

इनका कहना है

चंद्रबाबू नायडू ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है



नायडू ने तिरुमला मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाकर और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर पाप किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे आरोप नहीं लगा सकता। ये एक बार फिर साबित हो गया है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए नायडू हिचकेंगे नहीं। तिरुमला प्रसाद के मामले में मैं और मेरा परिवार ईश्वर की कसम खाने के लिए तैयार हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने परिवार के साथ कसम खाकर ये बात कहेंगे ?

वाईवी सुब्बारेड्डी, चेयरमैन,
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट

मंदिर में जाते हैं और प्रसाद खाते हैं, तो आप उसकी शुद्धता के बारे में सोचते होंगे। देश भर के लाखों हिंदू खुद से यही सवाल पूछ रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई चौंकाने वाली घटना कैसे सामने आई। यह चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ, जब प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों से लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में पशुओं की चर्बी मिले होने की पुष्टि हुई। और विवाद तब शुरू हुआ, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) की एक रिपोर्ट के आधार पर चिंता जताई। इसमें कहा गया था कि मंदिर में इस्तेमाल किया जाने वाला घी शुद्ध नहीं है। जांच में पुष्टि हुई कि घी आपूर्तिकर्ताओं में से एक, एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड ने मंदिर को आपूर्ति किए जाने वाले घी में पशुओं की चर्बी मिलाई थी। मंदिर को घी सप्लाई करने वाले निर्माता जब बाजार भाव से काफी कम दाम पर घी सप्लाई कर रहे थे, तब मंदिर संगठन से जुड़े लोगों को शक होने लगा। ऐसे में घी की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग उठने लगी। संदेह गहराने पर मंदिर को घी की आपूर्ति करने वाली सभी डेयरियों के घी की जांच कराई गई। बता दें

कि प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क और एआर डेयरी फूड तिरु मला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को घी सप्लाई करते थे।

मंदिरों में बढ़ गई सतर्कता

वहीं, इस घटना का असर पूरे भारत के अन्य मंदिरों पर भी पड़ा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में अधिकारी अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। प्रशासन ने मंदिर में बनाए जाने वाले लड्डुओं की शुद्धता की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में प्रसाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच करने के आदेश दिये गये।

लड्डू पहले भी विवाद में रहे

सितंबर 2024 की शुरुआत में लड्डू पाने के लिए टोकन दिखाने की व्यवस्था की गई है। एक लड्डू सबको फ्री में दिया जाता है। हां, अगर आपको एक लड्डू और हासिल करना है तो 50 रुपये चुकाने होंगे। श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड दिखाने की भी व्यवस्था की गई। जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए, वो आधार कार्ड दिखकर लड्डू हासिल कर सकते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए 7500 बड़े लड्डू और 3500 बड़ा बनाए जाते थे। 2008 तक एक लड्डू के

अलावा अगर किसी को प्रसाद चाहिए होता तो 25 रुपये में दो लड्डू दिए जाते थे। इसके बाद कीमत बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई। 2023 में इन लड्डुओं को ब्राह्मणों से बनवाए जाने से जुड़े एक नोटिफिकेशन पर भी विवाद हुआ था।

तिरुमला मंदिर और लड्डू

जो लड्डू चर्चा में हैं, उसे मंदिर के गुप्त रसोईघर में तैयार किया जाता है। ये रसोईघर पोटू कहलाता है। माना जाता है कि यहां हर रोज़ हजारों लड्डू तैयार किए जाते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों के अनुसार लड्डू, वडा, अप्पम, मनोहरम और जलेबी जैसे प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। इनमें से लड्डू सबसे पुराना और लोकप्रिय प्रसाद है। इसे प्रसाद के रूप में देने की परंपरा 300 वर्षों से चली आ रही है। तिरुमला में रोज़ साढ़े तीन लाख लड्डू बनाए जाते हैं। साल 2009 में तिरुपति के लड्डू को भौगोलिक संकेत या जियो ग्राफिकल इंडिकेटर दे दिया गया था। लड्डू को चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है। कहा जाता है कि इस लड्डू को बनाने का तरीका 300 साल पुराना है।



अर्चना शर्मा

साई बाबा के प्रति लोगों की आस्था दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि जगह-जगह पर साई बाबा के मंदिर बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक ओर जहां आस्था बढ़ रही है, वहीं इसके साथ एक विवाद भी सालों से चला आ रहा है कि साई वाकई ईश्वर थे या नहीं? अभी ताजा मामला वाराणसी के मंदिरों से साई बाबा की मूर्ति को हटाने को लेकर विवाद है। सनातन रक्षा दल द्वारा वाराणसी के मंदिरों से साई बाबा की मूर्ति हटाने की बात कही गई है। बाबा को लेकर समय-समय पर विवाद उत्पन्न होता रहा है। कभी उनके अस्तित्व को लेकर कभी उनकी पूजा करने पर। एक बार फिर साई बाबा को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल, वाराणसी के मंदिरों से साई बाबा की प्रतिमा हिंदू संगठनों द्वारा हटाई जा रही हैं। सनातन रक्षक दल की तरफ से इन प्रतिमाओं का हटाने का अभियान चलाया गया है। यहां सवाल उठता है कि क्या साई बाबा किसी एक धर्म के हैं या किसी एक वर्ग के हैं। यह बिल्कुल गलत है। साई बाबा किसी एक के नहीं बल्कि सबके हैं। साई बाबा को लेकर इस तरह विवाद खड़ा करना अनुचित है। वह करोड़ों लोगों की आस्था के केन्द्र हैं। साथ साई बाबा के मंदिर लाखों लोगों की आजीविका के साधन हैं। इन मंदिरों के आसपास से लोगों रोजी रोटी चलती है। इसके अलावा सरकार को किसी न किसी रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इस विवाद से भले ही कुछ लोग प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन देश के अंदर साई बाबा के अनुयायी भी करोड़ों की संख्या में हैं। निश्चित रूप से उनकी भावनाएं जरूर आहत हुईं होंगी। हम मानते हैं कि 20वीं सदी के महापुरुषों में शिरडी के साई बाबा को गिना जाता है। गरीबों, दुखियारों और अनाथों की निःस्वार्थ भाव से सेवा करके उन्होंने अपने आलोचकों तक का दिल जीत

साई बाबा किसी एक के नहीं सबके हैं

किसी साजिश के तहत तो नहीं जन्मा विवाद



लिया था। मानवता की सेवा में उनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने अपने इस काम में धर्म को कभी आड़े नहीं आने दिया और हर धर्म तथा समुदाय की चुपचाप सेवा की। महाराष्ट्र के शिरडी ग्राम को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया और जीवन भर वहीं रहे। वह हिन्दुओं के साथ दीवाली मनाते थे तो मुसलमानों के साथ ईद। उन्होंने धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं किया और अपना जीवन कमजोर तथा सर्वहारा वर्ग को अर्पित कर दिया। उन्हें हिन्दू-मुस्लिम एकता का एक ज्वलंत मिसाल माना जाता है। वह मानते थे कि धर्म चाहे जो भी हो ईश्वर एक है। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और वे एक फकीर से पूजनीय महापुरुष का दर्जा पाने में सफल हुए। आज देश-विदेश में बड़ी

तादाद में उनके अनुयायी हैं। शिरडी स्थित उनके मंदिर में लाखों भक्त हर साल उनकी आराधना करने और आशीर्वाद मांगने आते हैं।

उत्तरप्रदेश के वाराणसी से साईं बाबा को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ है। यहां पर बड़ा गणेश मंदिर और पुरूषोत्तम मंदिर से साईं प्रतिमाओं को हटाया गया है। मंदिर प्रबंधन की सहमति के बाद इन प्रतिमाओं को हटाया गया है। सनातन रक्षक दल सभी मंदिरों से इस प्रकार का अनुरोध कर रहा है। कई लोग साईं बाबा को एक संत और परम श्रद्धा का प्रतीक मानते हैं

उत्तरप्रदेश के वाराणसी से साईं बाबा को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ है। यहां पर बड़ा गणेश मंदिर और पुरूषोत्तम मंदिर से साईं प्रतिमाओं को हटाया गया है। मंदिर प्रबंधन की सहमति के बाद इन प्रतिमाओं को हटाया गया है। सनातन रक्षक दल सभी मंदिरों से इस प्रकार का अनुरोध कर रहा है। कई लोग साईं बाबा को एक संत और परम श्रद्धा का प्रतीक मानते हैं और उनकी मूर्तियों को मंदिरों से हटाए जाने को अनुचित मानते हैं। लोगों का कहना है कि साईं बाबा की पूजा से उनका जीवन शांति और सद्भाव में बीतता है और उन्हें एक धार्मिक विभाजन का हिस्सा बनाना अनुचित है। यह स्पष्ट है कि साईं बाबा की मूर्तियों को लेकर शुरू हुआ यह विवाद केवल वाराणसी तक सीमित नहीं रहेगा।



इस तरह की घटनाएं भविष्य में धार्मिक और सामाजिक तनाव का कारण बन सकती हैं। जहां एक तरफ ब्राह्मण महासभा पंच देवों की पूजा पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर जनता का एक बड़ा वर्ग साई बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त कर रहा है।

हम जानते हैं कि साई बाबा का जन्म और धर्म को लेकर ऐतिहासिक जानकारी न होने पर विवाद होते रहते हैं। यह माना जाता है कि साई बाबा ने जीवन भर किसी एक धर्म को विशेष रूप से नहीं अपनाया। उनके अनुयायी उन्हें एक संत मानते हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए सम्माननीय थे। साई बाबा का जन्म स्थान और उनके माता-पिता के बारे में भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जिससे यह पता चले कि वे किस धर्म से जुड़े थे। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम मानते हैं क्योंकि उनके रहन-सहन और शब्दावली में इस्लामी प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने अपने प्रवचनों में अक्सर

लाखों लोगों की आजीविका के साधन हैं साई बाबा के मंदिर

पूरे देश में हजारों की संख्या में साई बाबा के मंदिर बने हुए हैं। जहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। आस्था और श्रद्धा के साथ पहुंचे इन लोगों से यहां पर छोटे-छोटे रूप में व्यापार करने वाले लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। इनके परिवार पलते हैं। यह संख्या कम नहीं है। मंदिरों के आसपास धार्मिक सामग्री बेचते हैं, खाने पीने, रहने की व्यवस्था करते हैं जिससे इन लोगों को आमदनी होती है। शिरडी के साई बाबा मंदिर की ही बात की



जाये तो यहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर के कारण कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है। और मंदिर को भी आमदनी होती है। यह एक मंदिर की बात है ऐसे और भी कई मंदिर हैं। इसके साथ ही सरकार के खजाने में कर के रूप में काफी आमदनी होती है।



‘अल्लाह मालिक’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जो इस्लामी विचारधारा को दर्शाता है। साई बाबा को लेकर पहले भी कई बार विवाद हुआ है। कभी उनके जन्म को तो कभी उनके धर्म को लेकर।

कहां हुआ था साई बाबा का जन्म

साई बाबा कौन थे, क्या थे, इस बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। क्योंकि साई बाबा का कहां जन्म हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, यह एक रहस्य बना हुआ है। कोई उन्हें हिंदू बोलता है और कोई उन्हें मुसलमान कहता है। इसे लेकर लोगों के अलग-अलग मत बने हुए हैं। लेकिन, स्पष्ट रूप से किसी के पास कोई जानकारी नहीं है।

आखिरी हिंदू या मुस्लिम क्या था साई बाबा का धर्म ?

साई बाबा को लेकर कहा जाता है कि वह भारतीय गुरु, योगी और फकीर थे। एक

मत के अनुसार साई बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पाथरी (पातरी) गांव में 28 सितंबर 1835 को हुआ था। साई बाबा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के एक बड़ा हिस्सा मस्जिद में बिताया था। जिसे वह द्वारका माई कहते थे। हालांकि कभी भी साई बाबा ने अपने आप को किसी जाति के बंधन में नहीं बांधा। साई बाबा हिंदू और मुसलमान सभी के लिए समान भाव रखते थे। साई ने मानवता को अपना धर्म माना।

शिरडी में कब और कैसे पहुंचे साई बाबा

मान्यताओं के अनुसार, साई बाबा शिरडी में सबसे पहले वर्ष 1854 में दिखाई दिए थे। जिस वक्त वह शिरडी पहुंचे उस समय वह किशोरावस्था में थे। जब लोगों की उन पर नजर पड़ी तो वह नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। इसके बाद अचानक

ही वह शिरडी से गायब हो गए। फिर एक बार शिरडी में चांद पाटिल नाम के एक व्यक्तिकी बारात आई बारात के साथ ही साई बाबा एक बार फिर शिरडी पहुंचे। इसके बाद वह शिरडी के साई बाबा कहलाएं।

हिंदू-मुस्लिम धर्म से साई बाबा का जुड़ाव

उन्होंने कई मुस्लिम रिवाजों का पालन किया और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक मस्जिद में बिताया। दूसरी ओर, साई बाबा हिंदू रीति-रिवाजों का भी पालन करते थे जैसे कि दत्तात्रेय भगवान की पूजा और कई हिंदू देवताओं का सम्मान। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी किसी विशेष धर्म का पालन करने की सलाह नहीं दी। उनके विचारधारा के अनुसार सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही होता है- मानवता की सेवा और ईश्वर से जुड़ाव। इसलिए, यह कहना उचित होगा कि साई बाबा किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं थे, बल्कि वे मानवता और समभाव के प्रतीक थे। उनकी शिक्षाओं ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों को एकजुट किया और उनके जीवन का उद्देश्य धार्मिक मतभेदों को समाप्त करना था।

क्या कहना है अजय शर्मा का

सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा द्वारा बयान जारी किया गया है कि मंदिर प्रबंधन की मंजूरी मिलने के बाद की ऐसा किया जाएगा। अजय शर्मा ने कहा कि मैं साई का विरोधी नहीं हूँ। मैं साई की मूर्ति का विसर्जन कर रहा हूँ। उन्होंने सवाल किया कि गणेश मंदिर में साई का क्या काम है? अगर साई की पूजा ही करनी है तो अलग मंदिर बनाकर उनकी पूजा कराई जाए। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अजय शर्मा ने कहा कि काशी में केवल देवाधिदेव उमापति महादेव ही पूज्य हैं। शहर के मंदिरों में अज्ञानता के कारण साई की प्रतिमा स्थापित की गई। इससे सनातन भक्तों में नाराजगी है।

क्या मणिपुर और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है?



समता पाठक

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से जल रहा है। हाल ही में भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद भले ही वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा हो। लेकिन बांग्लादेश के बाद लगातार बंगाल और फिर मणिपुर की स्थिति को देखकर मन में काफी असंतोष है। असंतोष इस बात का भी है कि देश के प्रधानमंत्री ने अब तक न तो मणिपुर और न ही बंगाल के मामले में कुछ भी कहना उचित समझा। मणिपुर को हमने और आपने पिछले एक साल सभी अधिक समय से जलते हुए देख रहे हैं। लाशें गिर रही

है, लोग मर रहे हैं आपस में भिड़ रहे हैं लेकिन न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार

मणिपुर को हमने और आपने पिछले एक साल सभी अधिक समय से जलते हुए देख रहे हैं। लाशें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं आपस में भिड़ रहे हैं लेकिन न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार अभी तक इसका कोई हल ढूँढ पाई है।

अभी तक इसका कोई हल ढूँढ पाई है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर यह सब कितने दिन और चलेगा। आखिर कब मोदी सरकार इस पूरे मामले को शांत करने में सफल होगी।

मुख्यमंत्री बिस्वा को दी गई है जिम्मेदारी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच खाई पाटने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार.. लेकिन फिर भी हिंसा जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या



वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार एक महीने से भी ज्यादा समय से जारी तनाव और हिंसा को क्राबू में नहीं कर पा रही हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर के मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं?

लगातार दौरे हो रहे हैं फिर भी हालात खराब

गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के समय सभी पक्षों से बात कर 15 दिनों के भीतर शांति बहाल करने की अपील की थी लेकिन हालात और खराब ही होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात को ठीक करने के लिए जिस तरह के क़दम उठाए जाने की ज़रूरत थी वो क़दम ना केंद्र सरकार ने उठाए ना ही राज्य सरकार ने। सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के लोगों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा ख़ुद करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। और

इसी वजह से हालात बिगड़ते चले गए क्योंकि लोग हिंसा से निपटने के लिए ख़ुद हिंसा का ही सहारा ले रहे हैं।

मैतेई समुदाय शांतिपूर्वक रहते चले आए

विशेषज्ञ बताते हैं कि दोनों समुदायों के बीच लंबे समय से मतभेद होने के बावजूद

कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के लोगों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा ख़ुद करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। और इसी वजह से हालात बिगड़ते चले गए क्योंकि लोग हिंसा से निपटने के लिए ख़ुद हिंसा का ही सहारा ले रहे हैं।

राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय शांतिपूर्वक रहते चले आए हैं। यहां तक कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध भी रहे हैं लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनका एक दूसरे से भरोसा ही उठ गया है। मणिपुर में अब कुकी बहुल इलाके में कोई मैतेई क़दम रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वही दूसरी ओर मैतेई लोगों के इलाक़े में जाने का जोखिम कोई कुकी नहीं लेना चाहेगा।

हिंसा का ये दौर नहीं थमेगा

निनामबाम श्रीमा कहती हैं कि जब तक केंद्र सरकार बहुत मज़बूती से दख़ल नहीं देती है और राज्य सरकार आम लोगों की सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं करती है, तब तक हिंसा का ये दौर नहीं थमेगा। राज्य में काम कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता के. ओनील कहते हैं कि राज्य में जारी हिंसा से निपटने में जो गंभीरता केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए थी वो उसने दिखाई नहीं। गृहमंत्री अमित शाह का मणिपुर दौरा भी

महज़ खानापूर्ति था। उन्होंने किन्हीं ठोस उपायों की बात की ही नहीं।

शांति समिति के गठन को खारिज किया

एक तरफ कुकी जनजाति की सर्वोच्च संस्था कुकी इंपी ने शांति समिति के गठन को खारिज किया है। वहीं, मैतेई समुदाय का नेतृत्व कर रही कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रेटी ने इस शांति कमेटी में शामिल नहीं होने की घोषणा की है। के.

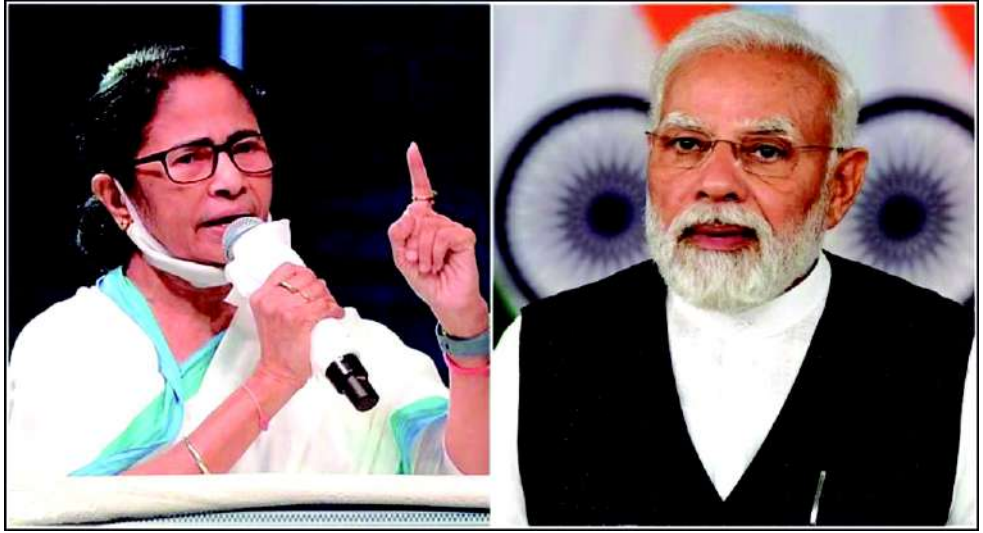
ओनील कहते हैं, “हालात सुधारने के मक़सद से सरकार ने जिस शांति समिति का गठन किया उसमें उन्होंने अपनी मज़ी से लोगों को शामिल किया। इस समिति में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो राज्य के, इस इलाक़े के हालात का विशेषज्ञ हो। ऐसे लोग जो राज्य को ठीक से समझते हों उन्हें समिति में होना चाहिए था। तो इसी बात से सरकार के इरादे समझ में आ जाते हैं।

जातीय विभाजन से उठी चिंकारी

राज्य में मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति के बीच जो जातीय विभाजन हुआ है उसे पाटने की ज़िम्मेदारी अब हिमंत बिस्वा सरमा को सौंपी गई है। लेकिन मणिपुर में ही कई लोग इससे ख़ुश नहीं हैं। मैतेई समुदाय के कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व को यह समझना चाहिए कि हिमंत बिस्वा सरमा उत्तर पूर्वी राज्यों की आवाज़ के प्रतिनिधि नहीं हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि हिमंत बिस्वा सरमा पूर्वोत्तर के बड़े नेता हैं और वे इस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं।

सुरक्षा संबंधी दिक्कतों के साथ महंगाई

राज्य में हिंसा की वजह से आम लोगों को सुरक्षा संबंधी दिक्कतों के साथ महंगाई



से भी जूझना पड़ रहा है। खाने-पीने की चीज़ों की क़ीमत में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हो गया है। लोगों को दवाइयाँ मिलने में परेशानी हो रही है। चावल कई जगहों पर दो सौ स्पए किलो तक मिल रहा है। एक महीने से जारी हिंसा के बावजूद अब तक सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है। कुकी जनजाति के सर्वोच्च छत्र निकाय कुकी छत्र संगठन ने इस पर नाराज़गी जताई है कि पीएम चुप हैं।

प्रधानमंत्री तक ठीक से बात नहीं पहुंचाई

निनगोमबाम श्रीमा ने आगे कहा, लोग मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बहुत ख़फ़ा हैं। उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ किया ही नहीं। मैतेई लोगों को इस बात का गुस्सा है कि राज्य विधानसभा में 60 में से 40 विधायक मैतेई समुदाय के हैं लेकिन इन विधायकों ने प्रधानमंत्री तक ठीक से बात नहीं पहुंचाई।

3 मई 2023 को शुरू हुई थी हिंसा

तीन मई को ये हिंसा तब शुरू हुई जब मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ राज्य के कुकी समेत दूसरे जनजातीय समुदाय ने रैली

निकाली जो बाद में हिंसक हो गई। उन्होंने मैतेई समुदाय पर हमले किए। जवाब में मैतेई समुदाय ने भी अपनी बदले की कार्रवाई शुरू कर दी और मैतेई बहुल इलाकों में रह रहे कुकी समुदाय के लोगों के घर जला दिए गए और उन पर हमले किए गए। इन हमलों के बाद मैतेई बहुल इलाकों में रहने वाले कुकी और कुकी बहुल इलाकों में रहने वाले मैतेई अपने-अपने घर छोड़कर जाने लगे।

संख्या में मैतेई लोग मारे जा रहे हैं

विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के पहाड़ी इलाकों से कुकी चरमपंथी मैतेई इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं जिससे बड़ी संख्या में मैतेई लोग मारे जा रहे हैं। राजधानी इंफाल तक में बेहद तनाव है। सीआरपीएफ़ के जवानों ने हमें सख्त हिदायत दी कि हम गाड़ी से बाहर ना निकलें। हिंसा का स्केल देखते हुए लगता है कि यहां कुकी और मैतेई समुदायों की आपसी रंजिश तो है ही साथ ही लगता है कि बाहर से भी आए चरमपंथी हिंसा में शामिल हैं। उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हो सकते हैं। फ़िलहाल राज्य में 40 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इससे समझा जा सकता है कि हालात कितने ख़राब हैं।



Does today's Indian democracy pass the Ambedkar test?

Aniket Gautam

The prevalent discourse on democracy seeking to counter Hindu nationalism has yet to consider Babasaheb Ambedkar's ideas on democracy. Ambedkar, a staunch social democrat, remains the untouched subject both by the progressive sections and mainstream media. Perhaps due to individual disagreements, any discourse on Ambedkar is set aside and the vast heritage of his conceptualization of democracy neglected. Just sample the speech "Conditions Precedent for the Successful Working of Democracy" Ambedkar delivered at the Poona District Law Library on 22 December 1952. He was there on an invitation to unveil the portrait of L.R. Gokhale and declare open to the public a set of newly donated books.

Ambedkar began his address by thanking the organizers for inviting him. Since he was professionally trained in a wide range of subjects, he asked the secretary of the library on what subject the audience wanted to hear him speak. He was given four topics and asked to choose one of them. He chose "Parliamentary Democracy", but tweaking it a little, he said he would speak on "Conditions Precedent for the Successful Working of Democracy", which according to him, was hugely important for a newborn India.

Before dealing with the subject matter, he decided to deal with several preliminary observations to provide what he called "a setting for the subject".

The first such observation Ambedkar made was "democracy is

always changing in its form". The ancient Greeks had their Athenian democracy, but, he noted, half the population were still slaves. Democracy in Athens was the exhibition of master-slave relations.

Second, "even in the same country democracy is not always the same". He supported his argument with the example of England. English democracy was not the same after the revolution of 1688. Democracy in England changed again after the reforms of 1832.

Third, Ambedkar noted, "democracy not only undergoes the change in its form, democracy always undergoes the changes in purposes". The purpose of the ancient English democracy was to prevent the king from exercising "prerogative rights". The resistance to autocratic

functioning of the king is what led to the emergence and development of democracy. Ambedkar clarified, "The purpose of modern Democracy is not so much to put a curb on an autocratic king but to bring about the welfare of the people." It is clear that Ambedkar here refers to the substance of democracy a mechanism to reach the common good.

After providing this background, he goes on to define democracy. Since it is a dynamic concept with no universally accepted concrete definition, it is unfair to assume larger consensus on certain sections of it. There have been many philosophers, political scientists, writers and thinkers who have contributed to the preconditions for a workable democracy. Out of all the theoretical contributions to democracy as a concept, Ambedkar referred to the two thinkers Walter Bagehot and Abraham Lincoln. Bagehot defined democracy as a "government by discussion". Ambedkar agreed with Walter Bagehot's definition of democracy. Another reference he

provides in his address is that of Abraham Lincoln, for whom democracy meant "government by the people, of the people and for the people". Analyzing predominant definitions of democracy, Ambedkar tried to arrive at his definition of democracy based on the material reality of the people of India. His definition of democracy reflected experiences of the existing social inequalities in India. He said democracy is "a form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed". His definition of democracy encompassed elements of a welfare state that intervened in public life to increase the capabilities of the weaker sections to achieve socio-economic equality. It is clear that for Ambedkar the practicality of such a definition was important. The severest test for a state to qualify as a democracy was for fundamental changes in social and economic life to take place without bloodshed. He said, "One has to read history and as

a result of reading history to find out the breakdown period in democracy's life in the different parts of the world where it had functioned and come to one's own conclusion". In the next section of his address, he touches upon the conditions precedent for the successful democracy.

Condition No. 1

According to Babasaheb Ambedkar, the first condition precedent for the successful working of the democracy is, "there must be no glaring inequalities in society". He elaborated, "there must not be any oppressed class and suppressed class". There shall not be a harsh distinction between the have and have-nots. The privileged section should not exploit the oppressed section. The ruling class should not enjoy the monopoly over wealth and resources. The oppressed class should not be forced to carry the burden of the entire society. The growing inequalities will result in devastation of democracy. This devastation may include rebellion or revolution. Establishment of any



political or social organization of society on the foundation of inequalities may result in bloodshed and discontent. Ambedkar remarked that “the deep cleavages between the class and class are going to be one of the greatest hindrances in the success of democracy”. Ambedkar was aware of the prevalent contradictions in the society. Historically, it is evident that parliamentary democracy has the

monarchy, those in power in a democracy have no perpetual authority to rule. The need for consent from the masses through elections held after every term puts restrictions on the rulers and forces them to regain trust for another term. Apart from this, there will be an “immediate veto”, that is, the unity of opposition in the parliament. The opposition in Parliament holds the government to account on decisions they make and

to be counterproductive to democracy and changed. He contrasted the “spoil system” with the system in England, where, Ambedkar writes, “in order that administration should remain pure, impartial, away from politics and policy, they have made a distinction between what is called political offices and civil offices. The civil service is permanent. It serves all the parties whichever is in office and carries out the administration without



potential to turn into tyranny with the suppression of minorities through manipulation and hegemonization.

Condition No. 2

Ambedkar spelt out the second condition for the successful working of a democracy as “existence of the opposition”. He explains the role opposition plays in a healthy democracy and the need for a veto of power. According to him, “Democracy is a contradiction of hereditary authority or autocratic authority. Democracy means that at some stage somewhere there must be a veto on the authority of those who are ruling the country.” Unlike the autocracy or

acts of omission and commission.

Condition No. 3

The third condition is equality in law and administration. This is done by keeping the judiciary and civil services as independent of the political offices as possible in the dispensation of their duties. A new party is voted to power but the judiciary and civil services remain unchanged. Ambedkar talked about the “spoil system” that was practised in the United States, when with a new party coming to power, the civil offices too down to the clerical positions were filled with the supporters of the government. This system was found

any kind of interference from the Minister.”

The Indian civil services too have been operating on a similar principle. But the central government's recent directive allowing central government employees to be part of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) goes against this principle of separating political and civil offices because the RSS is clearly a political organization promoting a Hindu nationalist agenda and the parent organization of the ruling BJP. Even with a permanent civil service, the influence of the RSS on the officers threatens equality in administration. Recently, a high court



what do we mean by free Government? Free Government means that in vast aspects of social life people are left free to carry on without interference of law, or if law has to be made, then the law maker expects that society will have enough morality in it to make the law a success." Surely, Ambedkar was alluding to the inherent lack of moral order in Indian society built on the caste system, under which the freedoms of a vast majority of the population is taken away at birth.

Ambedkar talked about the lack of "public conscience" in India. He defined public conscience thus: "Public conscience means conscience which becomes agitated at every wrong, no matter who is the sufferer and it means that everybody whether he suffers that particular wrong or not, is prepared to join him in order to get him relieved." He reminded the audience that the Whites were taking up the cause of the Blacks and Indians in South Africa but few in India spoke up against the segregation faced by Dalits if they weren't Dalits themselves. He said, "If this sort of thing happens, the minority which is suffering from injustice gets no help from others for the purpose of getting rid of this injustice, it again develops a revolutionary mentality which puts democracy in danger."

He concluded by warning the audience of the fragility of democracy. Democracy had survived in a handful of countries, he said, and that merely having won independence from the British and ratified a Constitution didn't mean that democracy was secure in India. "With all these examples before us, I think we ought to be very cautious and very considerate regarding our own future. You ought to consider whether we ought not to take some very positive steps in order to remove some of the stones and the boulders which are lying in our path in order to make our democracy safe."

judge resigned and joined the BJP, while another high judge declared on retirement that he is a lifelong member of the RSS.

Condition No. 4

The fourth condition is "constitutional morality". According to him, the written Constitution is a skeleton for which the flesh has to be found in constitutional morality. To explain constitutional morality, he gave the example of George Washington, the first president of the United States, who, despite having assumed a godlike status, initially refused to give in to demands to stand for a second term, because he said that would go against the purpose of the Constitution which was to replace the monarchical, hereditary rule. Eventually, he relented, became president for a second term but he didn't bow to pressure again at the end of the second term. It is easy to fall for emotions leaving behind the moral and ethical values. Constitutional morality is not a belief system. Instead it inculcates the knowledge system and awareness about the civil and political affairs of a

democratic state with positive results.

Condition No. 5

"There is one other thing which I think is necessary for the working of democracy and it is this that in the name of democracy, there must not be tyranny of the majority over the minority," said Ambedkar. His focus was on democracy within legislative bodies, especially in Parliament, about the majority party allowing debates on adjournment motions. At the time, the Congress party had a massive majority. The numbers were similarly in favour of the Bharatiya Janata Party (BJP) in its last term, 2019-24, when several crucial bills were bulldozed through Parliament with little or no debate.

After highlighting these aforementioned preconditions for a successful working of a democracy, Ambedkar concluded his address focusing on the issues of "Moral Order" and "Public Conscience". Predominantly, ethics and politics are dealt separately, which results in the moral order being taken for granted. Ambedkar said, "Democracy is spoken of as a free Government. And

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल



जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.
संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.